नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 04, अंक 199, नई दिल्ली, शनिवार 24 अक्टूबर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में सफलता केवल ऊँचा उठने में नहीं, बल्कि ऊँचा उठकर दूसरों को सहारा देने में है। सच्ची महानता वही है, जो दूसरों के जीवन में आशा, विश्वास और खुशियाँ भर दे।

03 वेद क्या हैं और उन्होंने दुनिया को क्या दिया?

06 अंतरात्मा का आईना: विशेषाधिकार अधिकार नहीं, जिम्मेदारी हैं

08 नाबालिग वाहन चालकों पर STA की नजर, पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना; 25 साल

दिल्ली-NCR के नाम पर जनता की परेशानी कब तक बढ़ेगी? 15 साल रोड टैक्स, 10 साल में रोक क्यों?

PUC पास वाहन को उम्र के आधार पर हटाना कितना उचित? - प्रदूषण नियंत्रण जरूरी, पर नियम पारदर्शी, व्यावहारिक और न्यायसंगत भी होने चाहिए

टेंपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
उपाध्यक्ष केके छाबड़ा और राष्ट्रीय महासचिव पिंकी कुंडू की ओर से हक की मांग

हम प्रदूषण नियंत्रण के विरोधी नहीं, समर्थक हैं। पर पर्यावरण और जनता के अधिकारों में संतुलन चाहिए। नियम पारदर्शी, व्यावहारिक और न्यायसंगत हों। मिलकर आवाज उठाओ! अब नहीं उठाई तो कब उठाओगे? जनता की समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

तथ्य एक नजर में

– समस्या: दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों पर NGT / सुप्रीम कोर्ट आदेशों के आधार पर प्रतिबंध

– जनता का तर्क: रोड टैक्स 15 साल का लिया जाता है, बीमा, फिटनेस, PUC — सब वैध, फिर गाड़ी 10 साल में स्क्रैप क्यों?

– दो प्रमुख माँगें: 1. प्रदूषण मानक पास करने वाले वाहनों को उम्र के आधार पर न हटाया जाए, वैधता बढ़ाने का विकल्प मिले। 2. पेट्रोल पंप पर बिना एथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल (Pure Petrol) भी विकल्प के रूप में मिले

– नारा: प्रदूषण कम करना जरूरी है, पर जनता की आवाज दबेगी नहीं!

मुख्य बिंदु — संवैधानिक और कानूनी आधार

– 1. मूल अधिकार — अनुच्छेद 19(1)(g) और 21: कोई भी नागरिक अपनी मेहनत की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार रखता है — जीवन, आजीविका और संपत्ति के संरक्षण का अधिकार

– 2. अनुच्छेद 300A — संपत्ति का अधिकार: विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। टैक्स पेड गाड़ी कानूनन संपत्ति है

– 3. मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989: वाहन की फिटनेस का आधार — उसका तकनीकी मानक और PUC, न कि केवल उम्र। नियम 52 के तहत रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का प्रावधान

– 4. न्यायिक आदेश बनाम राजपत्र अधिसूचना: NGT आदेश 2015 (Vardhaman Kaushik vs Union) और MC Mehta मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश — पर ये पर्यावरण संरक्षण के लिए हैं, इनमें PUC फेल वाहनों को हटाने पर जोर, पास वाहनों को नहीं। जनता माँग करती है कि वैज्ञानिक आधार पर पुनर्विचार हो

– 5. एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति: सरकार की E20 नीति (20% एथेनॉल) पर्यावरण के लिए, पर पुराने वाहनों और 2-व्हीलर में माइलेज और इंजन समस्या की शिकायत — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विकल्प चुनने का अधिकार

विस्तृत विश्लेषण — हक की मांग

1. टैक्स 15 साल, उपयोग 10 साल — यह कैसा न्याय? मध्यम वर्ग अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदता है। 15 साल का रोड टैक्स एडवांस, हर साल बीमा, PUC। अगर गाड़ी PUC पास है, फिटनेस ठीक है, तो उसे केवल कैलेंडर देखकर स्क्रैप में भेजना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। जर्मनी, UK, USA में भी उम्र नहीं, एमिशन टेस्ट देखा जाता है।

2. प्रदूषण का असली मापदंड क्या हो? प्रदूषण PUC मशीन से नापा जाता है। यदि 12 साल पुरानी डीजल कार BS-4 मानक पास कर रही है और 3 साल पुरानी कार फेल हो रही है, तो किसे हटाना चाहिए? नीति होनी चाहिए — Pollution Based, Not Age Based।

3. जनता के सवाल सरकार से

- क्या वाहन की उम्र से ज्यादा उसके वास्तविक प्रदूषण स्तर को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए?
- जब मालिक टैक्स, ग्रीन टैक्स, टोल देता है तो उसके हितों की रक्षा कौन करेगा?
- क्या E20 के साथ-साथ शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देना उपभोक्ता अधिकार नहीं है?
- क्या नीतियाँ बनाते समय छोटे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, मध्यम वर्ग की राय ली गई?

4. टेंपल ट्रस्ट की दो सूत्रीय माँग — केके छाबड़ा और पिंकी कुंडू

पहली माँग: जो वाहन निर्धारित PUC/BS मानकों को पूरा करता है, उसे उम्र के आधार पर प्रतिबंधित न किया जाए। उसकी वैधता को फिटनेस टेस्ट के आधार पर 3-5 साल बढ़ाने का विकल्प दिया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों में है।

दूसरी माँग: सभी पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ-साथ बिना एथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि उपभोक्ता अपनी गाड़ी की अनुकूलता के अनुसार चयन कर सके। यह उपभोक्ता के चयन के अधिकार का सम्मान है।

5. समाधान का रास्ता सरकार सार्वजनिक चर्चा करे, एक हाई-पावर कमेटी में वाहन मालिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों को शामिल करे। स्क्रैप नीति में उचित मुआवजा, टैक्स रिफंड, और फिटनेस बेस्ड सिस्टम लागू हो।

जनहित में जारी — टेंपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट – केके छाबड़ा, उपाध्यक्ष / पिंकी कुंडू, राष्ट्रीय महासचिव /



परिवहन विशेष समाचार पत्र | अक्टूबर 2026 विशेषांक | कानूनी विशेष

दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: रिटायर्ड MCD ड्राइवर को मिली राहत, 22 लाख का पूरा मुआवजा देगी नगर निगम

जस्टिस अनीश दयाल ने MAC अपील 402/2023 में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146(2) की सही व्याख्या की — सरकारी वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मुक्त, तो मुआवजे की जिम्मेदारी भी सरकार की

संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक एवं कानूनी परामर्श: टेंपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट

यह फैसला न्याय की उस मूल भावना को जीवित करता है कि ईश्वर है, अंधेर नहीं। एक रिटायर्ड, बेदाग रिकॉर्ड वाले ड्राइवर को 22 लाख के बोझ से मुक्त करना और जिम्मेदारी उस संस्था पर डालना जो कानूनन फंड रखने को बाध्य है — यही कानून की सही व्याख्या है। यह फैसला MCD जैसे सभी निकायों के लिए चेतावनी भी है कि वे अपने अनिवार्य दुर्घटना फंड को सक्रिय और पारदर्शी रखें।

तथ्य एक नजर में

– न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधीश जस्टिस अनीश दयाल

– केस: MAC अपील संख्या 402/2023 — रोहतास कुमार बनाम संगीता वर्मा व अन्य

– फैसले की तारीख: 16 अक्टूबर 2026

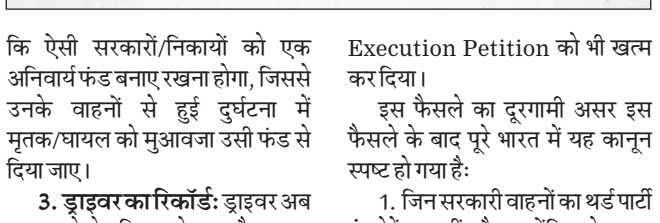
– मूल FIR: थाना द्वारका साउथ, MCD के टाटा ट्रक से हुई दुर्घटना में एक नौजवान की मौत

– ट्रायल कोर्ट आदेश: द्वारका MACT ने MCD और ड्राइवर रोहतास कुमार (निवासी गांव झरोदा, नजफगढ़) को संयुक्त/व्यक्तिगत रूप से 22 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

– अपील: MCD ने अपील नहीं की, ड्राइवर रोहतास कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी

मुख्य बिंदु — वकीलों की दलीलें

1. धारा 146(2) का संरक्षण: अधिवक्ता श्री विकासदीप शर्मा और श्री शफीक खान ने तर्क दिया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146(2) के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनके उपक्रम जैसे MCD थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से Exempted हैं।



कि ऐसी सरकारों/निकायों को एक अनिवार्य फंड बनाए रखना होगा, जिससे उनके वाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक/घायल को मुआवजा उसी फंड से दिया जाए।

3. ड्राइवर का रिकॉर्ड: ड्राइवर अब MCD से सेवानिवृत्त हो चुका है, उसका सेवा रिकॉर्ड शानदार रहा है, पूर्व में कोई दुर्घटना नहीं।

4. MACT ने अनदेखी की: द्वारका ट्रिब्यूनल ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया था।

ऐतिहासिक फैसला क्या है? माननीय जस्टिस अनीश दयाल ने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड, गवाहियां और धारा 146 को विस्तार से पढ़ने के बाद:

- रोहतास कुमार की अपील स्वीकार की।
- आदेश दिया कि पूरा मुआवजा ब्याज सहित MCD ही देगी, ड्राइवर को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं देना होगा।
- द्वारका जिला न्यायालय में चल रही Execution Petition को भी खत्म कर दिया।

इस फैसले का दूरगामी असर इस फैसले के बाद पूरे भारत में यह कानून स्पष्ट हो गया है:

1. जिन सरकारी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि वे धारा 146(2) में छूट प्राप्त हैं, उनके दुर्घटना मामलों में सरकार/निकाय ही पूरी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगी।
2. सरकारी वाहन चलाने वाले चालकों को व्यक्तिगत आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
3. पीड़ित परिवारों और घायलों को क्लेम मिलने में तेजी आएगी, क्योंकि फंड की जिम्मेदारी तय है।

नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेजों और अधिवक्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। पाठक अंतिम निर्णय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आदेश की प्रति अवश्य देखें।

परिवहन विशेष समाचार पत्र से जुड़े सभी पाठकों और सहयोगियों के लिए विशेष सूचना

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं की हम अपने चैनल के माध्यम से आपको 1. प्रतिदिन की देश विदेश की जानकारी 2. आपके वह आपके बच्चों के कैरियर, 3. आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित ज्ञानवर्धक आवश्यक जानकारिया, 4. आपकी सेहत से जुड़ी सभी उपयोगी जानकारियां 5. शारीरिक बीमारियों से बचने के तरीके 6. धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान विश्व के सभी क्षेत्रों के ज्ञानदाताओं के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हम अपने चैनल द्वारा प्रतिदिन एक घंटे के कार्यक्रम "जनता की पुकार" में आपकी आवाज को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सरकार और सरकारी विभागों के साथ माननीय न्यायालयों से उसके उचित हल और उसके प्रति पालिसी लागू करवाने में मध्यांतर का माध्यम बनेंगे। आप सभी से अनुरोध आप के अपने शुरू होने वाले चैनल के माध्यम से अपनी शिकायतें, परेशानियां और अनुभव अन्य सभी से साझा करने के लिए तैयार एवं तत्पर रहे। आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार : सोशल मीडिया टेकडाउन आदेशों में पारदर्शिता: प्राकृतिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय (अक्टूबर 2026)

Haryana 24 News Network Pvt. Ltd. v. Union of India मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक समाचार संस्था के फेसबुक पेज पर लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया। यह प्रतिबंध एक पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा जारी नोटिस के आधार पर लगाया गया था। न्यायालय ने कहा कि संबंधित अधिकारी के पास ऐसा नोटिस जारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं था, क्योंकि आईटी नियमों के नियम 3(1)(d) के तहत टेकडाउन निर्देश केवल विधिवत अधिकृत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।

न्यायालय ने यह भी पाया कि ऐसे नोटिसों के लिए निर्धारित अनिवार्य समीक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिससे उक्त कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर हो गई।

सबसे महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने निर्णय दिया कि भले ही आईटी नियमों में प्रभावित उपयोगकर्ता को टेकडाउन नोटिस की सूचना देने का स्पष्ट प्रावधान न हो, फिर भी प्रभावित पक्ष को सूचना देना प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) का एक अनिवार्य तत्व है। न्यायालय ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति को यह न बताया जाए कि उसके विरुद्ध किस आधार और किस सामग्री के आधार पर कार्रवाई की गई है, तब तक वह प्रभावी रूप से उस आदेश को चुनौती नहीं दे सकता।

तदनुसार, न्यायालय ने फेसबुक पेज को बहाल (Restore) करने का निर्देश दिया और यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी टेकडाउन कार्रवाई की स्थिति में संबंधित नोटिस की प्रति प्रभावित उपयोगकर्ता को शीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जब सरकार किसी सोशल मीडिया पोस्ट, पेज या अकाउंट को हटाने अथवा भारत में उसकी पहुँच प्रतिबंधित करने का निर्णय लेती है, तो आदेश सामान्यतः सीधे प्लेटफॉर्म को भेजा जाता है, न कि उस व्यक्ति को जिसने सामग्री प्रकाशित की है। परिणामस्वरूप, प्रभावित उपयोगकर्ता को अक्सर तभी पता चलता है जब सामग्री हट जाती है या उसकी पहुँच अवरुद्ध कर दी जाती है।

ऑनलाइन सामग्री हटाने के दो प्रमुख कानूनी प्रावधान

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A

– केंद्र सरकार को संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान करती है।

– इसकी प्रक्रिया आईटी (ब्लॉकिंग) नियम, 2009 के अंतर्गत संचालित होती है।

– ऐसे आदेश गोपनीय रखे जाते हैं, जिससे पारदर्शिता सीमित रहती है।

2. धारा 79(3)(b) एवं आईटी नियम, 2021 का नियम 3(1)(d)

– सरकार को मध्यस्थों (Intermediaries) को अवैध सामग्री हटाने के निर्देश देने का अधिकार देता है।

– फरवरी 2026 के संशोधन के बाद प्लेटफॉर्म को ऐसे नोटिस पर 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होती है।

– अनेक नोटिस गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संचालित सहयोग (Sahyog) पोर्टल के माध्यम से भेजे जाते हैं।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय (अक्टूबर 2026)

मामला Haryana 24 News Network Pvt. Ltd. v. Union of India में न्यायालय ने एक समाचार संस्था के फेसबुक पेज पर लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया।

न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

✓ केवल विधिक रूप से अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी ही टेकडाउन नोटिस जारी कर सकते हैं।

✓ ऐसे नोटिसों की अनिवार्य समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

✓ सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावित उपयोगकर्ता को टेकडाउन आदेश की सूचना देना आवश्यक है, भले ही नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख न हो।

न्यायालय ने माना कि उपयोगकर्ता को बिना सूचना दिए उसकी सामग्री हटाना प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के विपरीत है।

अक्टूबर 2025 संशोधन का महत्व

सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार:

– केवल वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ही नोटिस जारी कर सकते हैं।

– नोटिस लिखित एवं कारणयुक्त होना चाहिए।

– उसमें संबंधित कानूनी प्रावधान और हटाई जाने वाली URL का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

– सभी नोटिसों की मासिक समीक्षा अनिवार्य है।

– पुलिस की ओर से नोटिस केवल विशेष रूप से अधिकृत डीआईजी (DIG) या उससे उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

हालाँकि, इस संशोधन में भी प्रभावित उपयोगकर्ता को सूचना देने का प्रावधान नहीं था। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा इसी कमी को दूर किया।

धारा 69A और गोपनीयता का प्रश्न

धारा 69A के अंतर्गत जारी ब्लॉकिंग आदेश सामान्यतः सार्वजनिक नहीं किए जाते। इस कारण प्रभावित व्यक्ति अक्सर यह भी नहीं जान पाता कि उसके विरुद्ध किस आधार पर कार्रवाई की गई है। डिजिटल अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आदेशों में अधिक पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा की संभावना होनी चाहिए।

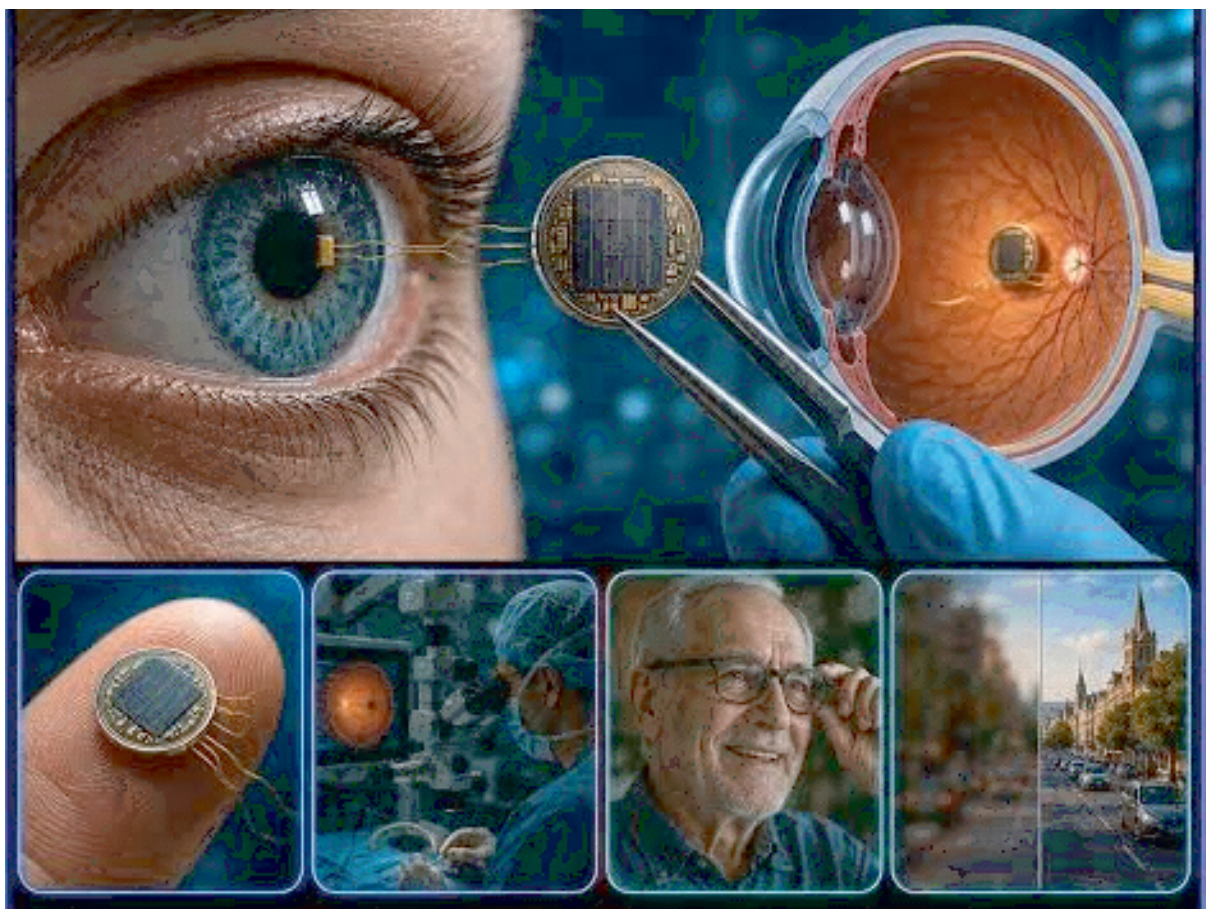
ऑनलाइन सामग्री का नियमन आवश्यक है, लेकिन पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया (Due Process) भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

"डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन तभी संभव है जब प्रभावित नागरिकों को कार्रवाई की जानकारी, सुनवाई का अवसर और कानूनी उपायों तक पहुँच प्राप्त हो।"

क्या आंखों की खोई रोशनी फिर लौट सकती है? विज्ञान से जगी नई उम्मीद

डॉ. विजय गर्ग

वैज्ञानिक उन जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जो रेटिना की कोशिकाओं को दोबारा विकसित होने से रोकती हैं। इस शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पीआरओएक्स-1 नामक प्रोटीन से संबंधित है। यह प्रोटीन कोशिकाओं के विकास और उनकी विशिष्ट पहचान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



दृष्टि मानव जीवन की सबसे अनमोल देन में से एक है। आंखों के माध्यम से हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं, परिचित चेहरों को पहचानते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग बीमारियों, चोटों और बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण दृष्टि खो देते हैं। लंबे समय से वैज्ञानिकों का मानना रहा है कि मानव आंख का क्षतिग्रस्त रेटिना स्वयं की मरम्मत करने की बहुत सीमित क्षमता रखता है। हालांकि, हाल के शोध ने एक नई संभावना जगाई है। क्या भविष्य में आंखें अपनी खोई हुई मरम्मत और पुनर्निर्माण की क्षमता फिर से प्राप्त कर सकेंगी?

रेटिना को समझना जरूरी है

रेटिना आंख के पिछले हिस्से में स्थित एक पतली, प्रकाश-संवेदनशील परत है। इसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें फोटोरिसेप्टर कहा जाता है। ये कोशिकाएं प्रकाश को महसूस करके उसे विद्युत संकेतों में बदलती हैं। ये संकेत ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जहां इनकी सहायता से हमें दृश्य दिखाई देते हैं।

जब रेटिना की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती हैं, तो दृष्टि काफी कमजोर हो सकती है। शरीर के कुछ अन्य ऊतकों के विपरीत, स्तनधारी जीवों के रेटिना में नष्ट हो चुकी तंत्रिका कोशिकाओं को दोबारा बनाने की प्राकृतिक क्षमता बहुत सीमित होती है। यही कारण है कि ग्लूकोमा और उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजनरेशन जैसी बीमारियां स्थायी दृष्टि हानि का कारण बन सकती हैं।

पीआरओएक्स-1 प्रोटीन की भूमिका

वैज्ञानिक उन जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जो रेटिना की कोशिकाओं को दोबारा विकसित होने से रोकती हैं। इस शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पीआरओएक्स-1 नामक प्रोटीन से संबंधित है। यह प्रोटीन कोशिकाओं के विकास और उनकी विशिष्ट पहचान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रयोगात्मक पशु मॉडलों पर किए गए शोध से संकेत मिले हैं कि पीआरओएक्स-1 कुछ रेटिनल कोशिकाओं की पुनर्जनन क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस प्रोटीन की कार्यप्रणाली को समझकर वैज्ञानिक उन जैविक प्रक्रियाओं को सक्रिय करने के तरीके खोज रहे हैं, जो स्तनधारी जीवों में सामान्यतः दबे रहते हैं।

चूहों पर किए गए प्रयोगों में संबंधित आणविक प्रक्रियाओं में बदलाव करने से रेटिना के पुनर्निर्माण और दृश्य क्षमता में सुधार के उत्साहजनक संकेत मिले हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि वयस्क स्तनधारी जीवों के रेटिना में ऐसी जैविक क्षमता हो सकती है, जिसे वैज्ञानिक अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं।

हालांकि, प्रयोगशाला में मिले उत्साहजनक परिणामों और प्रमाणित चिकित्सा उपचार के बीच अंतर समझना आवश्यक है। कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की सीमा, पीआरओएक्स-1 की वास्तविक भूमिका और उपयोगी दृष्टि की बहाली प्रयोग की परिस्थितियों तथा संबंधित कोशिकाओं पर निर्भर करती है। इस शोध का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्यों में पीआरओएक्स-1 प्रोटीन को प्राकृतिक रूप से कम करके खोई हुई दृष्टि वापस प्राप्त की जा सकती है।

ग्लूकोमा और मैक्युलर डिजनरेशन के मरीजों के लिए उम्मीद

दृष्टि हानि के दो प्रमुख कारण ग्लूकोमा और उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजनरेशन हैं।

ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। यह अक्सर आंख के भीतर बढ़े हुए दबाव से जुड़ा होता है। जब रेटिना की गैंग्लियन कोशिकाएं और उनके तंत्रिका तंतु नष्ट हो जाते हैं, तो वर्तमान उपचारों से उस क्षति को पूरी तरह ठीक करना सामान्यतः संभव नहीं होता। मौजूदा उपचारों का मुख्य उद्देश्य आंख का दबाव कम करना और आगे होने वाले नुकसान को रोकना है।

उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजनरेशन रेटिना के केंद्रीय भाग को प्रभावित करता है, जिसे मैक्युला कहा जाता है। यह भाग स्पष्ट और बारीक विवरण देखने के लिए जिम्मेदार होता है। बीमारी के प्रकार और अवस्था के अनुसार उपचार इसकी प्रगति को धीमा कर सकता है या दृष्टि के कुछ पहलुओं में सुधार ला सकता है। लेकिन नष्ट हो चुकी रेटिनल कोशिकाओं को दोबारा बहाल करना अभी भी विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है।

यदि वैज्ञानिक रेटिना की तंत्रिका कोशिकाओं को दोबारा विकसित करने, सहायक ऊतकों की मरम्मत करने और मस्तिष्क के साथ उनके प्रभावी संपर्क स्थापित करने के सुरक्षित एवं कारगर तरीके खोज लेते हैं, तो भविष्य में उपचार केवल बीमारी की प्रगति धीमी करने तक सीमित नहीं रहेंगे।

फिर भी, रेटिना के ऊतकों का दोबारा बनना अपने आप में दृष्टि लौटने की गारंटी नहीं है। नई कोशिकाओं को प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया देनी होगी, अन्य रेटिनल कोशिकाओं के साथ संवाद करना होगा और दृश्य तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक उपयोगी संकेत पहुंचाने होंगे।

प्रयोगशाला से मानव उपचार तक

रेटिना के पुनर्निर्माण को नियमित चिकित्सा उपचार बनाने से पहले कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना होगा।

सबसे पहले, वैज्ञानिकों को यह पता लगाना होगा कि चूहों पर प्राप्त परिणाम मनुष्यों में भी सुरक्षित रूप से दोहराए जा सकते हैं या नहीं। मानव आंख की संरचना अधिक जटिल है और विभिन्न प्रजातियों में जैविक प्रक्रियाएं अलग-अलग तरीके से काम कर सकती हैं।

दूसरा, कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सटीक रूप से नियंत्रित करना आवश्यक होगा। अनियंत्रित कोशिका वृद्धि या कोशिकाओं की पहचान में अवांछित बदलाव रेटिना की मरम्मत करने के बजाय उसे और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपचार से शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ने चाहिए।

तीसरा, दोबारा विकसित हुई कोशिकाओं का रेटिना के मौजूदा तंत्रिका नेटवर्क के साथ उचित तालमेल होना चाहिए। नई कोशिकाएं बनाना केवल एक चरण है। उपयोगी दृष्टि की बहाली के लिए पूरी दृश्य प्रणाली का एक साथ और सही ढंग से काम करना आवश्यक है।

अंत में, किसी भी संभावित उपचार की सुरक्षा, प्रभावशीलता, उचित खुराक और दीर्घकालिक परिणामों की पुष्टि नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से करनी होगी। इन चरणों के पूरा होने तक प्रयोगात्मक तरीकों को अंधेपन का प्रमाणित उपचार नहीं माना जाना चाहिए।

रोकथाम और समय पर जांच का महत्व

जब तक पुनर्जनन आधारित चिकित्सा विकसित हो रही है, तब तक मौजूदा दृष्टि की रक्षा करना सबसे व्यावहारिक उपाय है। आंखों की नियमित जांच से ग्लूकोमा, मधुमेह के कारण होने वाली आंखों की बीमारियों और अन्य समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है।

मधुमेह से पीड़ित लोगों को रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित रखना चाहिए और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार रेटिना की जांच करवानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि अचानक कम हो जाए, आंखों के सामने प्रकाश की चमक दिखाई दे, तैरते हुए धब्बे अचानक बढ़ जाएं या दृष्टि के सामने पर्दे जैसी छाया दिखाई दे, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

मरीजों को उन आई ड्रॉप्स, जड़ी-बूटियों से बने उत्पादों और अन्य सामग्रियों से भी सावधान रहना चाहिए, जिन्हें अंधेपन का प्राकृतिक इलाज बताकर बेचा जाता है, लेकिन जिनकी प्रभावशीलता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। कोई भी प्रमाणित घरेलू उपाय नष्ट हो चुके रेटिना को दोबारा बनाने या हर प्रकार की दृष्टि हानि को ठीक करने में सक्षम साबित नहीं हुआ है।

नेत्र विज्ञान में एक नई दिशा

रेटिना के पुनर्निर्माण की संभावना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के महत्वपूर्ण शोध क्षेत्रों में से एक है। पीआरओएक्स-1 जैसे प्रोटीनों पर शोध से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ कोशिकाएं अपनी पुनर्जनन क्षमता क्यों खो देती हैं और भविष्य में इस क्षमता को किस प्रकार फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

हालांकि, कई बीमारियों में अंधेपन का पूर्ण उपचार अभी दूर की संभावना है, लेकिन आणविक जीव विज्ञान, जीन थेरेपी, स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्जनन चिकित्सा में हो रही प्रगति नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है।

इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वैज्ञानिक प्रगति अक्सर उन धारणाओं पर सवाल उठाने से शुरू होती है, जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। पीआरओएक्स-1 से संबंधित शोध के माध्यम से खोई हुई दृष्टि की बहाली अभी प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन क्षतिग्रस्त रेटिना की मरम्मत के तरीके खोजने का प्रयास वैज्ञानिक दृष्टि से आशाजनक है।

दृष्टि संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए ये विकास सावधानीपूर्वक आशा रखने का कारण हैं। भविष्य में ऐसे उपचार विकसित हो सकते हैं, जो केवल बची हुई दृष्टि की रक्षा करने के बजाय खोई हुई दृष्टि के कुछ हिस्से को वापस पाने में भी मदद करें। तब तक निरंतर अनुसंधान, समय पर जांच और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नेत्र देखभाल अत्यंत आवश्यक हैं।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब – 152107

डायबिटीज से किडनी कैसे खराब होती है?

डायबिटीज से किडनी कैसे खराब होती है?

पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

सिर्फ 5 चरणों में समझें! लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ी रहने से किडनी को नुकसान हो सकता है।

1. बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लगातार बढ़ा हुआ ब्लड शुगर किडनी की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचा सकता है।
2. पेशाब में प्रोटीन बढ़ना किडनी को नुकसान होने पर पेशाब में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन बढ़ सकता है। इसके लिए UACR टेस्ट महत्वपूर्ण है।
3. किडनी की कार्यक्षमता कम होना किडनी की कार्यक्षमता जानने के लिए Serum Creatinine, eGFR और UACR टेस्ट उपयोगी हैं।
4. बीमारी का बढ़ना किडनी की कार्यक्षमता कम होने पर पैरों में सूजन, थकान और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।
5. गंभीर अवस्था किडनी की कार्यक्षमता बहुत कम होने पर कुछ मरीजों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।

डायबिटीज होने पर इन 4 बातों का ध्यान रखें!

✓ HbA1c — पिछले 2–3 महीनों के ब्लड शुगर नियंत्रण का अनुमान।
✓ eGFR — किडनी की कार्यक्षमता का आकलन।
✓ UACR — पेशाब में एल्ब्यूमिन की जाँच।
✓ ब्लड प्रेशर — रक्तचाप को नियंत्रित रखना।

किडनी को स्वस्थ रखने के 6 उपाय!

✓ ब्लड शुगर नियंत्रित रखें।
✓ ब्लड प्रेशर नियमित जाँचें।
✓ डॉक्टर की बताई दवाएँ नियमित लें।
✓ संतुलित आहार लें।
✓ नियमित व्यायाम करें।
✓ डॉक्टर की सलाह से किडनी की जाँच करवाएँ।

याद रखें! किडनी को शुरुआती नुकसान होने पर भी लक्षण दिखाई नहीं दे सकते। समय पर जाँच और सही उपचार से बीमारी की प्रगति धीमी करने में मदद मिल सकती है।

नोट: डॉक्टर की सलाह के बिना दवाएँ बंद या बदलें नहीं। अप्रमाणित हर्बल उपचारों पर निर्भर न रहें।



डायबिटीज़ को न करें नज़रअंदाज़ : आज की सावधानी, कल के बेहतर स्वास्थ्य की तैयारी!

डायबिटीज़ सिर्फ़ ब्लड शुगर बढ़ने का नाम नहीं है!

पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

शुरुआत में भले ही कोई परेशानी महसूस न हो, लेकिन लंबे समय तक ब्लड शुगर नियंत्रित न रहने पर हृदय, किडनी, आँखों और नसों पर बुरा असर पड़ सकता है।

बढ़ी हुई शुगर के संभावित लक्षण:

1. बार-बार पेशाब आना
2. बहुत अधिक प्यास लगना
3. बार-बार भूख लगना
4. थकान और कमजोरी
5. बिना कारण वज़न कम होना
6. हाथ-पैरों में झनझनाहट या जलन
7. आँखों से धुंधला दिखाई देना
8. घाव भरने में देरी
9. बार-बार संक्रमण होना
10. यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ

याद रखें: कई बार डायबिटीज़ में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसलिए नियमित जाँच बेहद ज़रूरी है।

अपनी सेहत के लिए इन जाँचों पर ध्यान दें:

1. ब्लड शुगर
2. HbA1c
3. ब्लड प्रेशर
4. लिपिड प्रोफाइल
5. किडनी फंक्शन टेस्ट
6. आँखों की जाँच

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें, सही पोषण को दें महत्व!

स्वस्थ जीवनशैली के साथ इन बातों पर भी ध्यान दें:

1. नियमित पैदल चलना और व्यायाम
2. संतुलित एवं पौष्टिक आहार
3. पर्याप्त नींद
4. तनाव को नियंत्रित रखना
5. नियमित स्वास्थ्य जाँच

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाएँ!

कुछ उपयोगकर्ताओं ने अपने अनुभवों में ऊर्जा, सक्रियता और शुगर रिपोर्ट में सुधार महसूस होने की बात कही है। हालाँकि, परिणाम हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना -डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी दवाएँ बंद या कम न करें।

आज सेहत का ध्यान रखें क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी सबसे बड़ी पूँजी है!



वेद क्या हैं और उन्होंने दुनिया को क्या दिया? - What Are the Vedas, and What Have They Given the World?

सनातन धर्म का आधार, मौखिक परम्परा से लिखित ज्ञान तक - श्रुति, अपौरुषेय और सत्य की खोज

Radhe-Radhe ji ! Hari Bol ! Jai Shri Radhe Krishn !

आपने बिल्कुल सही और संतुलित दृष्टिकोण रखा है। वेद सनातन धर्म में foundational स्थान रखते हैं और प्राचीन भारतीय धार्मिक, दार्शनिक और बौद्धिक परम्पराओं को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

1. वेद क्या हैं? चार वेद

- ऋग्वेद (Rigveda): विभिन्न देवताओं को समर्पित सूक्त, अस्तित्व की उत्पत्ति और प्रकृति पर गहन चिंतन। 10,600+ मंत्र।
- यजुर्वेद (Yajurveda): वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों से जुड़े मंत्र और विधियाँ, कर्तव्य का ज्ञान।
- सामवेद (Samaveda): मंत्रों को गायन और लयबद्ध रूप में व्यवस्थित - भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़।
- अथर्ववेद (Atharvaveda): स्तुतियाँ, प्रार्थनाएँ, घरेलू कर्मकांड, औषधियों और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा ज्ञान।

2. वेद कितने पुराने हैं? वेद पीढ़ियों तक मौखिक रूप से (श्रुति परम्परा) सुरक्षित रहे, बाद में पांडुलिपियों में लिखे गए। ऋग्वेद को चारों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इतिहासकार इसकी रचना आमतौर पर द्वितीय सहस्राब्दी BCE (Second Millennium BCE) में मानते हैं, हालांकि वेदों के विकास का सटीक कालक्रम अभी भी शोध का विषय है।

हिंदू परम्परा में वेदों को श्रुति माना जाता है और कई परम्पराओं में उन्हें अपौरुषेय - सामान्य मनुष्य द्वारा रचित नहीं, बल्कि ऋषियों द्वारा सुना गया ज्ञान - के रूप में समझा जाता है।

3. वैदिक परम्परा ने दुनिया को क्या दिया? वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय भाषा, काव्य, अनुष्ठान, धार्मिक विचार, मौखिक संचरण और बौद्धिक इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक भारतीय ज्ञान परम्परा ने गणित, खगोल विज्ञान, भाषा विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

लेकिन ऐतिहासिक सटीकता मायने रखती है: बाद की हर भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धि को स्वचालित रूप से चार वेदों से नहीं जोड़ा जा सकता। विशिष्ट दावों की जाँच संबंधित ग्रंथों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।



4. क्या वेदों में सभी आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान था? इस दावे को बिना साक्ष्य देखे स्वीकार या अस्वीकार नहीं करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में गहन अवलोकन, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और आज भी प्रासंगिक विचार हो सकते हैं। लेकिन किसी आधुनिक वैज्ञानिक खोज का श्रेय किसी प्राचीन ग्रंथ को तभी दिया जा सकता है जब उसका स्पष्ट, सत्यापनीय उद्धरण उस व्याख्या का समर्थन करे।

वैज्ञानिक दावों के लिए साक्ष्य, सटीक परिभाषाएँ और पुनरुत्पादनीय परीक्षण आवश्यक हैं। प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक व्याख्याओं को स्वतः वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

5. वेदों के अध्ययन से हम क्या सीख सकते हैं? हम उनके सूक्तों, दर्शन, अस्तित्व के बारे में विचारों, प्रकृति के साथ संबंध, आध्यात्मिक प्रथाओं और भारतीय सभ्यता के विकास में उनके स्थान का अन्वेषण कर सकते हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने से हमारी विरासत की समझ गहरी हो सकती है और साथ ही विचारशील जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिलता है।

हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए: प्राचीन ज्ञान का सम्मान करें, मूल स्रोतों का अध्ययन करें, ऐतिहासिक दावों की जाँच करें, और आध्यात्मिक विश्वास को वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य से अलग करना सीखें।

विरासत की सच्ची सराहना के लिए अतिशयोक्ति की आवश्यकता नहीं है। सत्य, ज्ञान और सच्ची जिज्ञासा ही इसे मजबूत बनाते हैं।

Jai Shri Radhe Krishn!



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

24 अक्टूबर 2026 | दिन का अंक: 8 — महत्वाकांक्षा, अधिकार, धन, अनुशासन और जिम्मेदारी

मूलांक 1

धन व करियर: दिन का अंक 8 आपकी नेतृत्व क्षमता में महत्वाकांक्षा, अधिकार और भौतिक फोकस बढ़ाता है। जिम्मेदारी लेने, शर्तों पर बातचीत और व्यावहारिक व्यवसायिक कदम के लिए अच्छा दिन है, बशर्ते रणनीति पर अहंकार हावी न हो।
रिश्ते: दो मजबूत ऊर्जाएं आपको निर्णायक लेकिन कम धैर्यवान बना सकती हैं। महत्वपूर्ण निर्णय सुनाने के बजाय सामने वाले को प्रक्रिया में शामिल करें।
सावधानी: प्रभुत्व, प्रतिष्ठा के लिए खर्च और मतभेद को अधिकार की लड़ाई बनाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अनुशासन से नेतृत्व करें और अपनी ताकत को परिणामों से साबित होने दें।

मूलांक 2

धन व करियर: दिन 8 आपकी संवेदनशील प्रकृति को आर्थिक रूप से अधिक दृढ़ बनने को कहता है। संयुक्त धन, फीस, भुगतान या पेशेवर सीमाओं की समीक्षा करें और उचित बात स्पष्ट रूप से रखें।
रिश्ते: आज मजबूत व्यक्तित्वों का दबाव महसूस हो सकता है। नरम रहें, लेकिन अपनी जरूरतें न छोड़ें और अपराधबोध को निर्णय न चलाने दें।
सावधानी: अपनी कीमत कम आंकने, भावनात्मक खर्च और विवाद से बचने के लिए तुरंत सहमत होने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण बातचीत में अंतर्ज्ञान के साथ स्पष्ट सीमा रखें।

मूलांक 3

धन व करियर: दिन 8 आपकी रचनात्मकता और संवाद को व्यवसायिक दिशा देता है। विचार पेशेवर तरीके से रखें, अपनी वैल्यू आत्मविश्वास से बताएं और मापने योग्य परिणाम देने वाले काम पर ध्यान दें।
रिश्ते: आपकी अभिव्यक्ति दिन के गंभीर स्वर को हल्का कर सकती है। गर्मजोशी रखें, लेकिन धन, जिम्मेदारी या प्रतिबद्धता से जुड़े विषय को मजाक में न टालें।
सावधानी: दिखावे के खर्च, बढ़ा-चढ़ाकर वादे और बिना ठोस आधार केवल पहचान के पीछे भागने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक रचनात्मक विचार को व्यावहारिक मूल्य में बदलें।

मूलांक 4

धन व करियर: दिन 8 आपकी अनुशासित प्रकृति के साथ मजबूत मेल रखता है। बजट, सिस्टम, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट या लंबी अवधि की व्यवसायिक योजना में धैर्यपूर्ण और व्यवस्थित कदम लाभ देंगे।
रिश्ते: जिम्मेदारियां आपका ध्यान अधिक ले सकती हैं। नियम और व्यावहारिक चिंताएं रिश्ते को किसी प्रोजेक्ट की तरह महसूस न कराएं।
सावधानी: कठोरता, निराशावाद और साझा धन या दिनचर्या पर अत्यधिक नियंत्रण से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक दीर्घकालिक आधार मजबूत करें और उचित सुझाव के लिए खुले रहें।

मूलांक 5

धन व करियर: दिन 8 आपकी तेज ऊर्जा को व्यवसायिक अनुशासन देता है। डील, बिक्री या नया संपर्क उपयोगी हो सकता है, लेकिन आर्थिक जोखिम लेने से पहले आंकड़े जांचें।
रिश्ते: स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की अपेक्षाओं में टकराव हो सकता है। योजना, धन और प्रतिबद्धताओं पर स्पष्ट रहें ताकि सहजता अविश्वसनीयता न लगे।
सावधानी: सट्टा, अचानक खरीदारी और थोड़े समय के उत्साह में दिशा बदलने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: लचीलेपन का उपयोग बेहतर बातचीत के लिए करें, जिम्मेदारी से बचने के लिए नहीं।

मूलांक 6

धन व करियर: दिन 8 धन, मूल्य और जिम्मेदारी पर मजबूत फोकस लाता है। गुणवत्ता की आपकी समझ क्लाइंट काम या आर्थिक योजना में लाभ दे सकती है, लेकिन विलासिता और आराम बजट के भीतर रहें।
रिश्ते: आज प्यार सुरक्षा और व्यावहारिक सहयोग से व्यक्त हो सकता है। धन को प्रेम या प्रशंसा का माप न बनने दें।
सावधानी: अपनों पर जरूरत से ज्यादा खर्च, अधिकार भावना और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आर्थिक बोझ उठाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: महंगे इशारे के बजाय समझदार निर्णय से सुरक्षा बनाएं।

मूलांक 7

धन व करियर: दिन 8 आपकी विश्लेषणात्मक प्रकृति को व्यावहारिक परिणाम की ओर धकेलता है। निवेश, कॉन्ट्रैक्ट या करियर रणनीति की जांच करें, फिर केवल विश्लेषण में रहने के बजाय स्पष्ट निर्णय लें।
रिश्ते: दबाव बढ़ने पर आप अधिक निजी हो सकते हैं। अपनी सोच समझाएं ताकि चुप्पी को अविश्वास या भावनात्मक दूरी न माना जाए।
सावधानी: संदेह, धन संबंधी गोपनीयता और पूर्ण निश्चितता के इंतजार में जरूरी कदम टालने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक सत्यापित समझ के आधार पर नपा-तुला व्यावहारिक कदम लें।

मूलांक 8

धन व करियर: आपके मूलांक 8 और दिन के अंक 8 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। महत्वाकांक्षा, अनुशासन, अधिकार, धन और कर्मिक जिम्मेदारी प्रमुख रहेंगे। गंभीर व्यवसायिक योजना, वसूली या दीर्घकालिक निर्णय के लिए अच्छा दिन है, यदि नैतिकता केंद्र में रहे।
रिश्ते: तीव्रता और नियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। सामने वाले की आवाज का सम्मान करें; स्थिरता दबाव से नहीं, न्यायपूर्ण व्यवहार से बनती है।
सावधानी: शक्ति संघर्ष, कठोर निर्णय, जोखिमपूर्ण आर्थिक दबाव और काम में अत्यधिक डूबने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करें और एक महत्वपूर्ण आर्थिक या पेशेवर दायित्व पूरा करें।

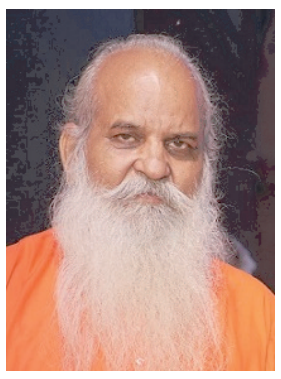
मूलांक 9

धन व करियर: दिन 8 आपकी उद्देश्यपूर्ण ऊर्जा को भौतिक संरचना देता है। उदारता को योजनाबद्ध रखें, आर्थिक दायित्व पूरे करें और संसाधन वहां लगाएं जहां दीर्घकालिक प्रभाव बन सके।
रिश्ते: आप सबकी रक्षा की जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं। अपनों का सहयोग करें, लेकिन उन्हें अपने निर्णय और जिम्मेदारी स्वयं निभाने दें।
सावधानी: अपराधबोध में खर्च, दूसरों को आर्थिक रूप से बचाने और अन्याय पर नाटकीय प्रतिक्रिया से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: सबका बोझ उठाए बिना अपनी शक्ति को एक अर्थपूर्ण परिणाम में लगाएं।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes

Vediccodes - Your vibrations... our solutions

(करवा चौथ हास्य व्यंग्य) गाँठ-गाँठ रस होय



डा. विनोद बब्बर

करवा चौथ निकट आते ही सोशल मीडिया पर सर्वत्र हास-परिहास, व्यंग्य, वक्रोक्तियां बिखरी हुई नजर आती है। सच ही है जितनी कविताएं, व्यंग्य, चुटकुले पति-पत्नी की नोंक झोंक पर है उतनी शायद ही किसी अन्य विषय पर हो। कारण हजार हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण है इस रिश्ते जैसी जीवान्तता शायद ही किसी अन्य रिश्ते में हो। लगभग हर पत्नी कहती है- 'ये तो मैं ही हूं जो आपके जैसे के साथ निभा लिया। अगर कोई दूसरी होती तो .....!'

पति भी कहां कम है- 'रहने दे, तेरी जैसी छत्तीस मिलेगी।'

ध्यान से देखिये। अगर दूसरी की जरूरत पड़े तो पति को उसी जैसी ही चाहिए। एक विदुषी से हमने हर पत्नी की उपरोक्त गर्वोक्ति के बारे में जानना चाहा तो उनका कहना था, 'दूसरी होती तो.... तो... वह भी तो .. !' में कुछ गलत कहां है। एक बार एक शरीफ पुलिस अधिकारी ने एक डाकू को कहा, 'खबरदार ! एक कदम भी आगे बढाया तो.. तो.. !' डाकू ने पूछा, 'तो.. तो.. क्या?' शरीफ का जवाब था, 'तो.. तो.. मैं दो कदम पीछे हो जाऊंगा।' अरे भाई भारतीय नारी है। दूसरी होती तो वह भी इन्हीं संस्कारों से युक्त होती। वह भी निभाती लेकिन कहती जरूर, 'अगर कोई दूसरी होती तो..... !' आप कम से कम इस मामले में हम महिलाओं के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह न ही लगाये तो ठीक वरना..... वरना..... !'

मामला फिर धमकी पर आकर अटक गया तो अपुन ने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। सुना है उनके पास सर्जिकल आपरेशन के लिए चिमटा, बेलन जैसे इसे अमोघ अस्त्र-शस्त्र होते हैं।

हमारे एक मित्र विदेश गये तो पत्नी को साथ ले गये। पत्नी दिनभर में कई बार दुलारती, 'ध्यान से खाना नहीं खा सकते क्या? देखो कपड़ों पर सब्जी लग गई है।' तो कभी 'देखो कपड़े गंदे कर लिए। आपको तो बैठने तक की तमीज नहीं, बिन देखे बैठ जाते हो।' इसे संयोग कहिये या दुर्योग कि उस यात्रा में मैं भी साथ था। एक दिन हमारे मित्र ने बाजार से डरते-डरते कुछ खरीद लिया लेकिन रास्ते में मुझे बोले- आज भी जाते ही सुनना पड़ेगा- 'आपकी तो पसंद ही इतनी घटिया है कि बस ... ! बिना सोचे समझे जो मिले घर ले आते हो !' मैंने उन्हें उन्हें एक गुरु मंत्र दिया। यकीन मानिये, उस दिन के बाद उन्हें 'आपकी तो पसंद ही.....!' वाला जुमला फिर कभी नहीं सुनने को नहीं मिला। आपके दिल की धड़कन बता रही है कि आप भी वही 'गुरुमंत्र' लेना चाहते हो जिसने हमारे मित्र की पसंद को घटिया बताने से बढ़िया में बदला। वैसे बता दूं मुफ्त की दवा असर नहीं करती इसीलिए तो आजकल बाबाओं के रेट है। पहले से ऑनलाइन, अप्वाइंटमेंट, पेमैंट लेकर मिलने का प्रचलन है। लेकिन अपुन फिलहाल इतने व्यापारी नहीं है। मुफ्त में भी कोई नहीं पूछता तो... तो..... ! खैर छोड़िए। मतलब की बात पर आते हें। मैंने उन्हें समझाया- अब जब भी आपकी देवीजी कहे, 'आपकी तो पसंद ही..... !' तो आप फौरन कहना, 'ठीक ही कह रही हो। मुझे बढ़िया की ही आदत होती तो सोच लो आप भी यहां न होती।' मंत्र मारक था। उस दिन तो काम कर गया। आप इसका उपयोग अपने रिस्क पर चाहे तो कर सकते हैं। बिना कुछ लिए-दिए गारंटी- वारंटी का कोई प्रावधान नहीं है।

इधर एक भुगतभोगी ने पूछा, 'चौथ शब्द को परिभाषित करें। अक्सर सुनने में आता है कि फलां चौथ वसूली में धर लिया गया। क्या चौथ वसूली और करवाचौथ में कोई संबंध है?' प्रश्न भयंकर था। उत्तर देने पर दक्षिण की ओर मुंह करने की



नौबत भी आ सकती थी इसलिए कया जरूरी है दक्षिणायण को आमंत्रित किया जाय। अपुन इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। अगर आप शब्दावली चयन आयोग से कुछ संबंध रखते है तो इस अंतर पर प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उत्तर आपके अंतरतम से ही आना चाहिए।

एक साहब का दर्द छलका, 'बाजार तो महिलाओं के कारण ही चल रहे है। फैशन के नाम पर कीमती डैस, कास्मैटिक, जेवर, ब्यूटर पार्लर और न जाने क्या-क्या। कभी खरीददारी का जरूरत से संबंध हुआ करता था। आज खरीददारी जरूरत का नहीं, जुर्रत का मामला बन गया है। जवानी से बुढ़ापे तक अपुन की वही पेंट कमीज लेकिन उनका तो हर दिन नया फैशन। हे राम ! कुछ करो !'

अनचाहे ही मुंह से निकला, 'आपने रॉग नम्बर डायल कर दिया है। हमारे रामजी क्या करेंगे? जवानी में वनवास में रहे। लौटे तो धोबी ने माता सीता को वनवास दिलवा दिया। उन्हें तो शायद फरमाईशों और जरूरतों का ठीक से अनुभव भी नहीं हुआ होगा।'

खैर चलते-चलते इतना और बताना चाहता हूं कि हमारे एक परिचित के दूसरा पुत्र हुआ तो पहले पुत्र के जन्म से भी अधिक प्रसन्न दिखाई दिये। हमने पूछा तो बहुत गहरी बात कही, 'बंधु, बेशक कहने को सभी जिंदगी भर प्यार, मोहब्बत मांगते हैं लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं चल सकती। भोजन की थाली में सिर्फ मीठा नहीं होता। कुछ चटपटा भी चाहिए। कुछ मिर्च भी होनी चाहिए। आदमी आदमी है। न जाने कब, दिमाग घूम जाये और बिना बात सिर पर सवार होने की सोच ले। एक बेटा आखिर झगड़ता भी तो किससे झगड़ता। पड़ोसी से नोक-झोंक करे तो हाथ पाव तुड़वाने से जेल जाने तक का खतरा है। अब दो भाई हो गये- एक दूसरे का सहारा बनेंगे और कभी मन हुआ तो आपस में.....!'

अपने मित्र की स्मृति को प्रणाम करते हुए आज करवाचौथ पर समस्त मातृशक्ति का अभिनन्दन करता हूं जो हमारे 'जैसे-तैसे' भाईयों, बेटों और उनकी इज्जत को 'जैसे-तैसे' बचाये हुई है। आप ही हमारी संस्कृति का प्राणाधार हैं। हमारी शक्ति है। हम सबकी प्रेरणा है। दुनिया की हर कविता आपके त्याग, समर्पण की प्रतिछाया है। हर संगीत आपकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। ये ऋचुएं आपके पराक्रम ही कारण पूरे परिवार का बल और श्रृंगार बनती हैं। कोई माने या न माने लेकिन आदिमानव को 'सुसंस्कृत' इंसान केवल और केवल आपकी ममता और विश्वास ने बनाया है।

चलते चलते बता दूं कि एक युवा दंपत्ति बाबाजी की कुटिया में पधारे तो इधर-उधर की चर्चा में बिटिया बोली, 'बाबा करवाचौथ का चांद से क्या संबंध हो सकता है।' अब यह अनाड़ी बाबा क्या बताता, मुख से केवल इतना ही निकला, 'बेटा, चांद शीतलता का प्रतीक है तो कुछ लोगों को उसमें दाग ही दिखाई देता है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने दांपत्य को सूत्र दिया है - अंधेरे में चमको लेकिन शीतल भी रहो और हाँ अगर थोड़ा बहुत दाग भी हो तो भी निभाओं !

समस्त मातृशक्ति के श्रीचरणों में नमन करते हुए रहीम को भी स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने कहा है-

जहाँ गाँठ तहँ रस नहीं, यह रहीम जग जोय।
मँड़ए तर की गाँठ में, गाँठ गाँठ रस होय।।

भांकरोटा के अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर का दो दिवसीय वार्षिक मेला शनिवार से

--- आर्यिका विष्णुप्रभा माताजी ससंघ का होगा मंगल प्रवेश, दो दिन धर्म, भक्ति और श्रद्धा के साथ होंगे विविध आयोजन

जयपुर। राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित भांकरोटा के अति प्राचीन एवं अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर का दो दिवसीय वार्षिक मेला शनिवार एवं रविवार को आर्यिका विष्णुप्रभा माताजी ससंघ के सानिध्य में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ आयोजित होगा। मेले के दौरान श्रीजी के कलशाभिषेक, शांतिधारा, मंगल प्रवचन, विधान पूजन एवं सामूहिक गोठ सहित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम होंगे।

अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक जैन बिट्टू एवं मेला मुख्य संयोजक नगेन्द्र सेठी ने बताया कि मेले के प्रथम दिन शनिवार को प्रातः 6 बजे आर्यिका विष्णुप्रभा माताजी ससंघ का कमला नेहरू नगर दिगंबर जैन मंदिर से विहार प्रारंभ होगा। अजमेर रोड बस स्टैंड होते हुए बैंड-बाजों एवं जैन धर्म के जयकारों के बीच माताजी ससंघ का मंदिर परिसर में भव्य मंगल प्रवेश होगा। इसके पश्चात आर्यिका संघ के सानिध्य एवं मुखारविंद से श्रीजी के कलशाभिषेक एवं शांतिधारा का आयोजन होगा। इस अवसर पर आर्यिका श्री विष्णुप्रभा माताजी श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वचन प्रदान कर धर्म एवं जीवन मूल्यों का संदेश देंगी।

उन्होंने बताया कि वार्षिक मेले का मुख्य आयोजन रविवार को प्रातः 7 बजे श्रीजी के कलशाभिषेक एवं शांतिधारा के साथ प्रारंभ होगा। प्रातः 8 बजे आर्यिका श्री विष्णुप्रभा माताजी के मंगल प्रवचन होंगे। इसके पश्चात प्रातः 9:30 बजे आर्यिका संघ की आहारचर्या संपन्न होगी तथा सुबह 11:15 बजे आर्यिका संघ के सानिध्य में विधान पूजन प्रारंभ होगा। पूजन के पश्चात आमंत्रित अतिथियों एवं आयोजन में सहयोग देने वाले सहयोगियों का सम्मान एवं अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद समाज की सामूहिक गोठ का आयोजन होगा। संध्याकालीन सत्र में श्रीजी की महामंगल आरती की जाएगी। तत्पश्चात ब्रह्मचारिणी शैली दीदी के प्रवचन होंगे, जिनके साथ दो दिवसीय वार्षिक मेले का समापन होगा।

अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि वार्षिक मेले में जयपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाओं के सम्मिलित होने की संभावना है। यह आयोजन समाज को धर्म, संस्कार, भक्ति एवं सामाजिक एकता के सूत्र में जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

अभिषेक जैन बिट्टू

शीर्षक - रास पूर्णिमा (गोपी छंद)

शरद पूर्णिमा की रश्मियाँ, अमृत
"आनंद" बहाती है,
शुभागमन में शरद ऋतु के, प्रकृति
गीत गुनगुनाती है ।

देख आज कण-कण धरा का, पूर्ण
रसामृत से है भरा,
सुधाकर सोलह कला लिए, व्योम
में झूमता मुस्कुरा,
श्वेत शांति का ये तोहफ़ा, धरा को
निशाकर से मिला,
दिव्य अमिय माधुर्यता से, रोम-रोम
पुलकित हो खिला,
चाँदनी शरद पूर्णिमा की, प्राण
शुद्धि को बढाती है,
शुभागमन में शरद ऋतु के, प्रकृति
गीत गुनगुनाती है ।

धवल आभ ने ब्रह्माण्ड में,
तिलिस्म प्रेम का बिखेरा,
स्पर्श ने चाँदनी के नया, खुशी का
भाव है उकेरा,
भूलकर दु:ख चकोर यही, किसी
प्रेम राग में खोया,
पारिजात ने कपोलों में, नेह
'आनंद' को पिरोया,
रास पूर्णिमा की रात ये, प्रसन्नता
को जगाती है,
शुभागमन में शरद ऋतु के, प्रकृति
गीत गुनगुनाती है ।

हुई भक्ति में श्री कृष्ण की, भाव
विभोर सभी गोपियाँ,
अनूठी कृपा सांवरे की, नवान्न
पूनम करें खुशियाँ,
भक्त खीर का प्रसाद बना, प्रेम से
भोग है लगाते,
भजन रातिजोगा कर सभी,
हरिप्रिया को है मनाते,
कौमुदी पूर्णिमा सभी को, शक्ति
सम्पन्न बनाती है,
शुभागमन में शरद ऋतु के, प्रकृति
गीत गुनगुनाती है ।

- मोनिका डागा "आनंद", चेन्नई



मतदाता सूची पुनरीक्षण में रखी जा रही पूर्ण पारदर्शिता : जिला निर्वाचन अधिकारी

6 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों के साथ की एसआईआर के कार्यों की समीक्षा

28 अक्टूबर तक पूरी होगी शेष नोटिस की सुनवाई



झज्जर, 23 अक्टूबर

जिला झज्जर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 का कार्य पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे। इसी दिशा में सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ए. श्रीनिवास ने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसआईआर अभियान की समीक्षा की। इस दौरान झज्जर जिला में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जिले में एसआईआर के तहत चल रही गतिविधियों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए सभी अधिकारी पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए और पुनरीक्षण से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं।

डीसी ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी किए गए नोटिस पर सुनवाई का कार्य जारी है। शेष नोटिस की सुनवाई 28 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाने और सुनवाई की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो तथा प्रत्येक मामले का नियमानुसार निपटारा किया जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का भी नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने, फॉर्म-7 के माध्यम से नाम हटाने संबंधी दावे तथा फॉर्म-8 के माध्यम से विवरण में संशोधन सहित अन्य निर्धारित सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर निपटारा सुनिश्चित करें।

मतदाता सूची के संबंध में जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक जारी प्रारूप मतदाता सूची में जिले के कुल 6 लाख 68 हजार 832 मतदाता दर्ज हैं। जिले के सभी 807 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों की तैनाती की गई है। इनके कार्यों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि एसआईआर अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके और किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके।

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के निर्देशानुसार अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनरीक्षण से जुड़े शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करें। साथ ही, मतदाताओं से संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अंतिम मतदाता सूची त्रुटिरहित और विश्वसनीय हो।

बैठक में एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, सीटीएम ऋतु, उप तहसीलदार निर्वाचन कुलदीप सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला पुरस्कारों के लिए 5 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन : डीसी

परिवहन विशेष न्यूज

नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगा, युवा शक्ति को दें सकारात्मक दिशा : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने एनकॉर्ड बैठक में नशा तस्करी से जुड़े मामलों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

नशे के खिलाफ अभियान में शिक्षा विभाग की अहम भूमिका, विद्यार्थियों को जागरूक करने के दिए निर्देश

डीसी ने कहा-नशे के नेटवर्क पर निगरानी के साथ शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाएं जागरूकता

झज्जर, 23 अक्टूबर

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा

कि नशे की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए भी व्यापक अभियान चलाया जाए।

डीसी शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में एनकॉर्ड (नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन) बैठक के दौरान नशा नियंत्रण से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। इससे पहले मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनकॉर्ड की समीक्षा प्रदेश में सभी उपायुक्त से समीक्षा की।

डीसी ने बैठक में कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी विभाग निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुरूप गंभीरता से कार्य करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने निर्देश दिए कि नशा तस्करी से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।

आमजन की भागीदारी से नशे पर लगेगी रोक

डीसी ने कहा कि नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। आमजन की भागीदारी से नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशा नियंत्रण से जुड़े प्रयासों की नियमित समीक्षा की जाए और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जिला प्रशासन नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करने और नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्कूल में ई-शपथ और प्रार्थना सभा के माध्यम से जागरूकता

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में विद्यार्थियों को ई-शपथ भी शिक्षण संस्थान में दिलाई गई है। साथ ही, स्कूल की प्रार्थना सभाओं में नशे के दुष्प्रभावों, इसके सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी नुकसान और नशे से दूर रहने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डीसी ने इन जागरूकता गतिविधियों को निरंतर जारी रखने पर कहा कि विद्यार्थियों में शुरुआत से ही नशे के प्रति जागरूकता विकसित करना आवश्यक है। स्कूल स्तर पर चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम बच्चों को सही निर्णय लेने और अपने परिवार एवं समाज में भी नशा विरोधी संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

नशा तस्करी पर निगरानी और प्रभावी कार्रवाई जरूरी

डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और सूचना मिलने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखा जाए। साथ ही, नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार और परामर्श की सुविधाओं से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त झज्जर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और आमजन की सहभागिता महत्वपूर्ण है।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर डीसीपी फैसल खान, एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगा, युवा शक्ति को दें सकारात्मक दिशा : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने एनकॉर्ड बैठक में नशा तस्करी से जुड़े मामलों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

नशे के खिलाफ अभियान में शिक्षा विभाग की अहम भूमिका, विद्यार्थियों को जागरूक करने के दिए निर्देश

डीसी ने कहा-नशे के नेटवर्क पर निगरानी के साथ शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाएं जागरूकता



झज्जर, 23 अक्टूबर

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि नशे की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए भी व्यापक अभियान चलाया जाए।

डीसी शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में एनकॉर्ड (नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन) बैठक के दौरान नशा नियंत्रण से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। इससे पहले मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनकॉर्ड की समीक्षा प्रदेश में सभी उपायुक्त से समीक्षा की।

डीसी ने बैठक में कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी विभाग निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुरूप गंभीरता से कार्य करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने निर्देश दिए कि नशा तस्करी से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।

आमजन की भागीदारी से नशे पर लगेगी रोक

डीसी ने कहा कि नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। आमजन की भागीदारी से नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशा नियंत्रण से जुड़े प्रयासों की नियमित समीक्षा की जाए और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जिला प्रशासन नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करने और नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्कूल में ई-शपथ और प्रार्थना सभा के माध्यम से जागरूकता

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में विद्यार्थियों को ई-शपथ भी शिक्षण संस्थान में दिलाई गई है। साथ ही, स्कूल की प्रार्थना सभाओं में नशे के दुष्प्रभावों, इसके सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी नुकसान और नशे से दूर रहने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डीसी ने इन जागरूकता गतिविधियों को निरंतर जारी रखने पर कहा कि विद्यार्थियों में शुरुआत से ही नशे के प्रति जागरूकता विकसित करना आवश्यक है। स्कूल स्तर पर चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम बच्चों को सही निर्णय लेने और अपने परिवार एवं समाज में भी नशा विरोधी संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

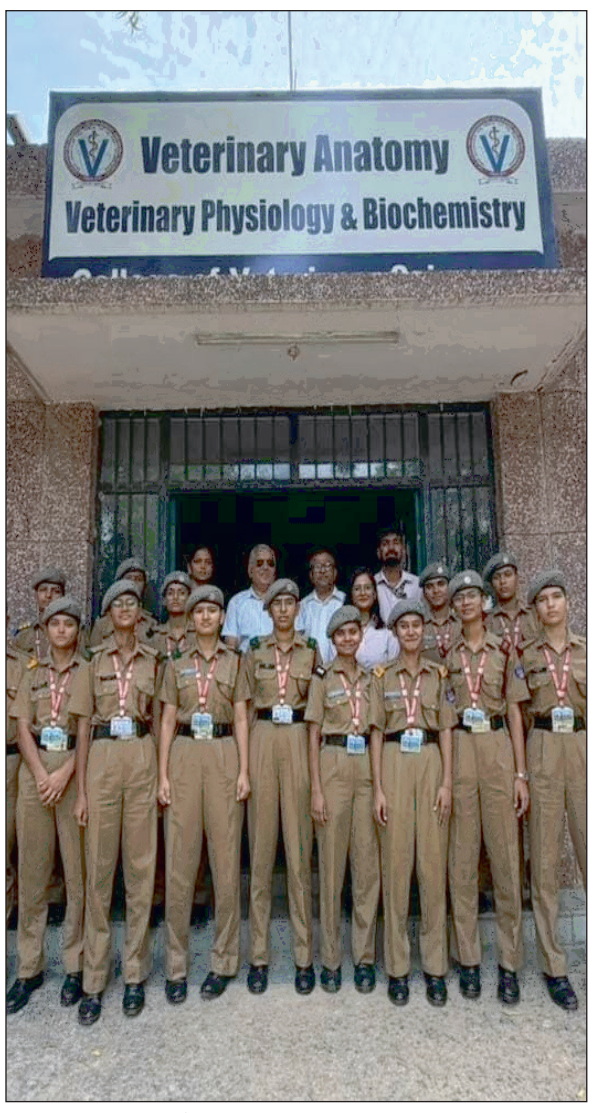
नशा तस्करी पर निगरानी और प्रभावी कार्रवाई जरूरी

डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और सूचना मिलने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखा जाए। साथ ही, नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार और परामर्श की सुविधाओं से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त झज्जर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और आमजन की सहभागिता महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रयासों और निरंतर जागरूकता से युवाओं को नशे से दूर रखने तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर डीसीपी फैसल खान, एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

सैनिक स्कूल खारा खेड़ी के 105 कैडेट्स ने किया लुवास का शैक्षणिक भ्रमण



हरियाणा हिसार// राजेश सलूजा

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), हिसार में सैनिक स्कूल खारा खेड़ी, जिला फतेहाबाद की कक्षा दसवीं के 105 कैडेट्स ने शैक्षणिक भ्रमण किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार वर्मा तथा पशुचिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. (डॉ.) अनीश यादव के मार्गदर्शन में आयोजित इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति तथा भविष्य में उपलब्ध शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों से अवगत करवाना था।

भ्रमण के दौरान कैडेट्स ने पशुचिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों का अवलोकन किया। विशेष रूप से पशु शरीर रचना विज्ञान विभाग के संग्रहालय में उन्होंने पशुओं की शारीरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विश्वविद्यालय के पशु फार्म के विभिन्न अनुभागों का दौरा कर घरेलू पशुओं के प्रबंधन, देखभाल एवं पालन-पोषण की प्रक्रियाओं को समझा। इसके बाद कैडेट्स ने पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर (वीसीसी) का भ्रमण किया, जहां उन्होंने बीमार पशुओं के उपचार की प्रक्रिया को नजदीक से देखा और पशु चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल की।

इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान कैडेट्स को पशु चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों, उनमें प्रवेश की प्रक्रिया तथा भविष्य में उपलब्ध करियर के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी गई। यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी रहा, क्योंकि इससे उन्हें दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बाद अपनी शैक्षणिक धारा और भविष्य के करियर का चयन करने में सहायता मिलेगी।

इस शैक्षणिक भ्रमण का संचालन लुवास के डॉ. गौरव गुप्ता ने किया। कैडेट्स के साथ सैनिक स्कूल के कमांडेंट कर्नल (डॉ.) डी.वी. नेहरा (सेवानिवृत्त), शिक्षक श्री रोहित नांदल एवं सुश्री मोनिका तथा प्रशिक्षक नायक संजीव (सेवानिवृत्त) एवं श्री अजय कायत भी उपस्थित रहे।

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों को भी मिले पर्याप्त अवसर : एसडीएम जगदीश चंद्र





एसडीएम ने गांव कोयल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर मिड-डे मील और विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा

हरियाणा/हिसार (राजेश सलूजा) नरवाना एसडीएम जगदीश चंद्र ने वीरवार को उपमंडल के गांव कोयल स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का दौरा कर शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी संतोष देवी, बेलरखां विद्यालय के प्राचार्य बलजीत गोयत, रविन्द्र कुमार और गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता, विद्यालय में साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, पढ़ाई के स्तर और खेल गतिविधियों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

एसडीएम जगदीश चंद्र ने मिड-डे मील का निरीक्षण करते हुए भोजन की गुणवत्ता और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के साथ विद्यालय परिसर में नियमित रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध सुविधाओं, कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। एसडीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर विशेष ध्यान दें और विषयों को सरल व प्रभावी तरीके से समझाएं। पढ़ाई में किसी विद्यार्थी को कठिनाई हो तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर प्रदर्शन कर सके।

एसडीएम जगदीश चंद्र ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। खेल गतिविधियां बच्चों के शारीरिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए विद्यालयों में शिक्षा और खेल के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उन्हें खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। एसडीएम ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और उनकी सफलता में शिक्षकों व अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और समय के सदुपयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से भी आह्वान किया कि वे बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए निरंतर प्रयास करें।

एसडीएम ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, बैठने की सुविधा और खेल गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासन की ओर से समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं, ताकि व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जा सकें।

पेंशनभोगी खजाना कार्यालय में 01 नवंबर से जमा करवाएं जीवन प्रमाणपत्र : डीटीओ

-ऑनलाइन प्रमाण पत्र स्मार्टफोन के माध्यम से हो सकते है जमा

- जिला कोषाधिकारी संजय फोगाट ने दी जानकारी

झज्जर, 23 अक्टूबर। जिला खजाना कार्यालय व उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित खजाना कार्यालय के साथ-साथ अन्य माध्यम से भी अपना जीवित होने का प्रमाण दर्ज करवा सकते हैं। ये जानकारी जिला कोषाधिकारी संजय फोगाट ने दी।

उन्होंने बताया कि यह सुविधा सभी डाकघरों द्वारा भी घर पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके लिए निर्धारित शुल्क का प्रावधान रखा गया हैं। यह ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र सुविधा सभी कॉमन सर्विस सेंटरों व अटल सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन प्रमाण पत्र स्मार्टफोन के माध्यम से भी जमा करवाया जा सकता हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई फीस का प्रावधान नहीं हैं, यह निशुल्क है।

कोषाधिकारी ने बताया कि परिवार को कोई भी सदस्य अपने स्मार्टफोन के माध्यम से उक्त कार्य को स्वयं कर सकता हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र फेस ऐप तथा दूसरा आधार फेस आरडी दोनों सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन से इंस्टाल करने होंगे तद-उपरांत किसी भी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खजाना कार्यालय में आरंभिक दिनों में ज्यादा भीड़ ना बने इसके लिए आपको सूचित किया जाता है कि ज्यादा उम्रदराज सम्मानित बुजुर्ग अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए स्वयं आने पर विचार करें, ताकि आरंभिक दिनों में ज्यादा परेशानी से बचा जा सके।

पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड (मूल प्रति), पैनकार्ड व पीपीओ की फोटो प्रति अवश्य साथ लेकर आएं तथा मोबाईल फोन जो पेंशन खाते से जुड़ा हो ओटीपी के लिए साथ लेकर आएं।

आज भी ये लोग आजादी से वंचित जीवन जी रहे हैं... समाजसेवी नामदेव भोसले की प्रेरक यात्रा

14 स्कूल बदले, 46 गांवों में भीख मांगकर गुजारा – फिर भी शिक्षा ने बनाया अनुकरणीय समाजसेवी, आदिवासी छात्रों को दिया उज्ज्वल भविष्य का मंत्र

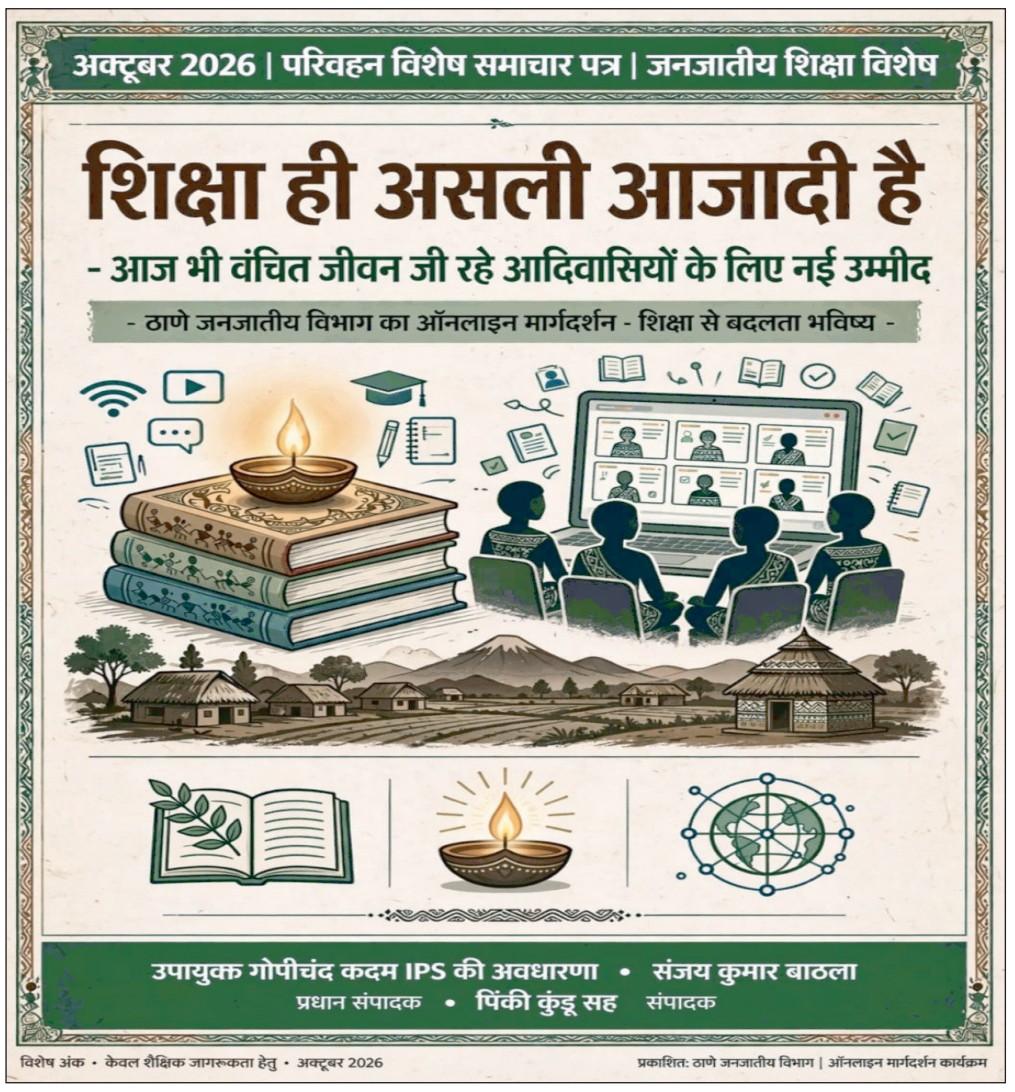
लेखिका:- सुरेखा भोसले - जनजातीय शिक्षा विशेष - संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक। पिंकी कुंडू, सह संपादक - परिवहन विशेष समाचार पत्र

तथ्य

- स्थानः ठाणे, जनजातीय विभाग ऑनलाइन मार्गदर्शन सत्र
- मुख्य व्यक्तित्वः समाजसेवी नामदेव भोसले, उपायुक्त गोपीचंद कदम (IPS) की अवधारणा
- उपस्थितः सहायक आयुक्त राहुल शिरके, केसर सिंह अहिरे, जनजातीय आयुक्त कार्यालय के अधिकारी
- संदर्भः पुणे जिला और पश्चिमी महाराष्ट्र के आदिवासी आज भी मूलभूत आजादी और सुविधाओं से वंचित

मुख्य बिंदु

1. संघर्ष से शिखर तकः नौवीं तक 14 स्कूल बदले, बचपन में 46 गांवों में भीख मांगकर जीवनयापन — विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा नहीं छोड़ी
2. सत्र का उद्देश्यः आदिवासी छात्रों में शैक्षिक जागरूकता, आत्मविश्वास और शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य का निर्माण
3. संदेशः शिक्षा केवल नौकरी का साधन नहीं, जीवन बदलने की शक्ति है — गरीबी और कठिनाइयों से निराश न हों
4. आज की हकीकतः आजादी के 78 साल बाद भी कई आदिवासी समुदाय आजादी से वंचित जीवन जी रहे हैं —



उन्हें उचित मार्गदर्शन और अवसर चाहिए

विस्तृत विश्लेषण ठाणे जनजातीय विभाग द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन सत्र में नामदेव भोसले ने सैकड़ों छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को यदि सही मार्गदर्शन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं।

यह पहल उपायुक्त गोपीचंद कदम (IPS) की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग छात्रों को ऑनलाइन प्रेरित करते हैं।

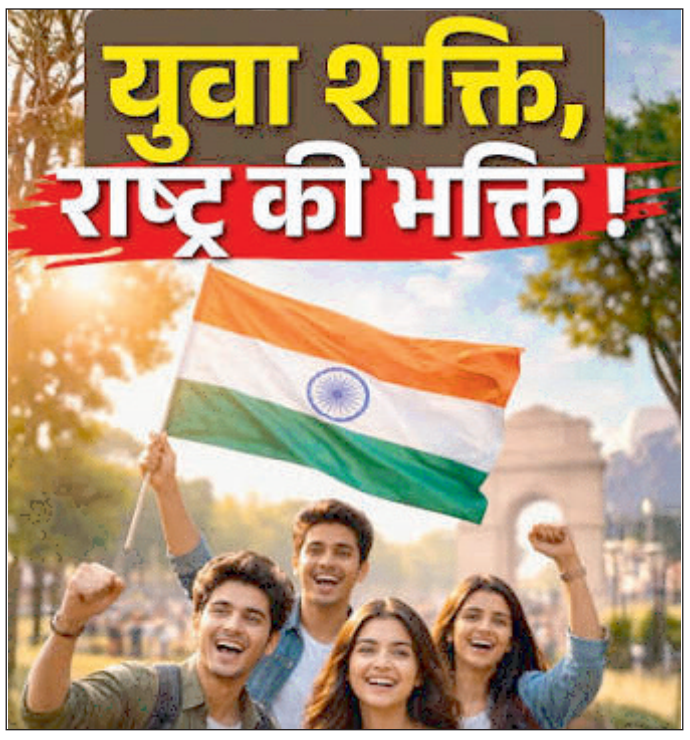
संपादकीय टिप्पणी: नामदेव भोसले की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, शिक्षा की जीत की कहानी है। जब समाज का वंचित वर्ग भी शिक्षा से जुड़ेगा, तभी सच्ची आजादी आएगी।

राष्ट्र की रीढ़ युवा हैं, लेकिन क्या उन्हें न्याय और समान अवसर मिल रहे हैं? डॉ विक्रम चौरसिया

भारत की आजादी महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। उनका सपना केवल स्वतंत्र भारत नहीं, बल्कि ऐसा राष्ट्र था, जहां हर नागरिक को सम्मान, न्याय और समान अवसर मिले। आज सवाल है क्या हम उनके सपनों के भारत की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं?

लोकतंत्र केवल मतदान नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचने का विश्वास है।जब किसी गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार को अपनी शिकायत लेकर थाने में सुनवाई के लिए संघर्ष करना पड़े, या किसी पीड़ित को उपेक्षा का अनुभव हो, तो व्यवस्था को आत्ममंथन करना चाहिए। कानून की नजर में हर नागरिक समान है उसकी जाति, धर्म, पहनावा या आर्थिक हैसियत न्याय का आधार नहीं बननी चाहिए।दूसरी ओर, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरें उन युवाओं के सपनों को चोट पहुंचाती हैं, जो वर्षों की मेहनत और परिवार के त्याग के सहारे भविष्य बनाना चाहते हैं। जब प्रश्नपत्र लीक होता है, तो केवल परीक्षा की गोपनीयता नहीं टूटती, ईमानदार युवाओं का भरोसा भी डगमगाता है। इसलिए पारदर्शी व्यवस्था और दोषियों के विरुद्ध कानूनसम्मत कठोर कार्रवाई जरूरी है।

राजनीति से लेकर रोजगार तक, अवसरों का आधार योग्यता, परिश्रम और ईमानदारी होना चाहिए, न कि अनुचित सिफारिश या प्रभाव। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही भी लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करती है।भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले



रहा है। लेकिन विकास केवल आधुनिक इमारतों, तकनीक और आर्थिक समृद्धि का नाम नहीं है। जहां सड़कें तो आधुनिक हों, लेकिन न्याय तक पहुंच कठिन हो जहां प्रतिभा हो, लेकिन अवसर समान न हों वहां विकास अधूरा है।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी आवश्यक है। हम व्यवस्था से ईमानदारी की अपेक्षा करें, तो स्वयं भी ईमानदार बनें भेदभाव का विरोध करें, तो अपने व्यवहार में समानता अपनाएं और अन्याय के विरुद्ध संवैधानिक तरीके से आवाज उठाएं। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार की नहीं, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

आज जरूरत केवल विकसित भारत के नारे की नहीं, ऐसे भारत के निर्माण की है जहां गरीब की आवाज सुनी जाए, युवा की मेहनत सुरक्षित रहे और न्याय किसी की हैसियत का मोहताज न बने।स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सच्चा सम्मान तभी होगा, जब हर नागरिक को न्याय, सम्मान और अवसर मिले। क्योंकि राष्ट्र की असली ऊंचाई उसकी इमारतों से नहीं, नागरिकों के सम्मान से मापी जाती है और लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता में नहीं, न्याय में बसती है।

चिंतक/ मेंटर/ एक्टिविस्ट/ टीवी पैनलिस्ट

एक व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट हत्या का आरोप और सुप्रीम कोर्ट का फैसला!

Mobile में chat होना ही गुनाह का सबूत नहीं! डिजिटल युग में न्याय का बड़ा सवाल

विश्लेषण - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया

डिजिटल क्रांति में जांच बदली है, पर न्याय का सिद्धांत नहीं - AI, Deepfake, स्क्रीनशॉट के दौर में अदालतों को सत्यता की कड़ी परीक्षा लेनी होगी। यह फैसला व्हाट्सएप के विरुद्ध नहीं, बिना पुख्ता प्रमाण के सजा के विरुद्ध न्यायिक सावधानी है।

तथ्य एक नज़र में

- केस: कुसुमलाल साव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | Criminal Appeal No. 4994/2026 (SLP Crl 11542/2026)
- पीठ: जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई | Neutral Citation: 2026 INSC 1148
- निर्णय तिथि: 13 अक्टूबर 2026 (चर्चा 23 अक्टूबर 2026)
- मूल घटना: 9 फरवरी 2019 - सौरभ पांडा का शव खुले मैदान में मिला, मोटरसाइकिल और रस्सी पास में
- निचली अदालत: IPC 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) में दोषी, हाईकोर्ट ने बरकरार रखा

मुख्य बिंदु

1. व्हाट्सएप संदेश: PW-5 और PW-6 के फोन के बीच 7-8 फरवरी की रात का संदेश, जिसमें कथित विवाद का जिक्र - अभियोजन ने इसे मुख्य आधार बनाया
2. गवाह मुकरे: दोनों गवाहों ने आंखों देखी



घटना से इनकार किया, एक ने कहा भैंने ऐसा संदेश भेजा ही नहीं

3. धारा 6 की व्याख्या: Res Gestae - मौत का समय ही तय नहीं, तो संदेश उसी घटनाक्रम का हिस्सा कैसे?
4. धारा 65-B / 61-63: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अस्तित्व अलग है, उसमें लिखी बात का सच होना अलग - प्रमाणपत्र और स्रोत जरूरी
5. भौतिक साक्ष्य में विरोधाभास: खून लगी मिट्टी, लोहे की रॉड, शर्ट की बरामदगी - जगह को लेकर विरोधाभास, DNA मिलान नहीं, मोटरसाइकिल से गिरने की वैकल्पिक संभावना खारिज नहीं

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

- व्हाट्सएप चैट/स्क्रीनशॉट अकेले हत्या साबित नहीं कर सकते
- संदेह और दोषसिद्धि में अंतर - संदेह का लाभ आरोपी को
- परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी कड़ी जरूरी, डिजिटल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता, लेखक की पहचान और स्रोत सिद्ध करना होगा
- अपील स्वीकार, आरोपी बरी

बामड़ा जैसे ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन पर जनसंवाद के नाम पर खानापूर्ति, रेलवे प्रशासन की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल

स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों को सूचना तक नहीं; जनसंवाद की प्रक्रिया पर भड़का जनाक्रोश, दोबारा आयोजन की मांग

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र बामड़ा।

ऐतिहासिक महत्व रखने वाले बामड़ा रेलवे स्टेशन पर जनसंवाद के नाम पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर स्थानीय क्षेत्र में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आम नागरिकों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन ने स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों को न तो समुचित जानकारी दी और न ही उन्हें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब जनता की भागीदारी ही सुनिश्चित नहीं की गई, तो यह जनसंवाद आखिर किसके लिए और किस उद्देश्य से आयोजित किया गया?

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे जनसंवाद का मूल उद्देश्य यात्रियों की समस्याओं, क्षेत्रीय आवश्यकताओं, रेल सुविधाओं और स्टेशन के विकास से जुड़े मुद्दों पर जनता की राय सुनना होता है। लेकिन यदि संबंधित लोगों को सूचना तक नहीं दी जाए, तो



ऐसी प्रक्रिया जनसंवाद के बजाय महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। बामड़ा जैसे ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के संदर्भ में इस तरह की कार्यशैली को स्थानीय नागरिक गंभीर उपेक्षा के रूप में देख रहे हैं।

रेलवे प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए नागरिकों का कहना है कि कागजों पर कार्यक्रम आयोजित कर देना और वास्तविक जनभागीदारी सुनिश्चित करना दो अलग-अलग बातें हैं। यदि जनता को विश्वास में लिए बिना ही प्रक्रिया पूरी कर ली गई, तो इसे पारदर्शी और सार्थक जनसंवाद कैसे माना जा सकता है?

स्थानीय क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच मांग उठ रही है कि रेलवे प्रशासन तत्काल संज्ञान लेते हुए जनसंवाद का दोबारा आयोजन करे। इस बार स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संबंधित हितधारकों को समय रहते विधिवत सूचना देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

बामड़ा के नागरिकों का स्पष्ट संदेश है कि ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन की गरिमा और स्थानीय जनता की आवाज को नजरअंदाज कर जनसंवाद की औपचारिकता पूरी करना स्वीकार्य नहीं है। रेलवे प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। जनसंवाद जनता के लिए है, न कि केवल फाइलों में आयोजन दर्ज कराने के लिए।

भाजपा की डॉआस्था ने मुस्कुराते हुए भेजी और सपा के हेमराज बड़े प्रेम से हंसते हुए खाई चाय और पकौड़ी

पकौड़ी कूटनीति' से पीलीभीत की राजनीति में भूचाल क्या चुनावी जंग सिर्फ दिखावा है।

हरिओम बाजपेई, नादान'।

कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन। लेकिन के एम एल सी चुनाव के दौरान घटी एक दिलचस्प घटना ने इस कहावत को एक नया मोड़ दे दिया है। यहाँ चुनावी मैदान में आमने-सामने सीना ताने खड़े धुर विरोधी दलों के बीच 'गरमा-गरम चाय और पकौड़ी' ने ऐसी बाजी मारी कि राजनीतिक दूरियाँ एक पल में हवा हो गईं। एमएलसी चुनाव के दौरान माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। बीजेपी और सपा दोनों ही खेमे अपने-अपने 'चुनावी बिस्तर' लगाकर एक-एक वोटर को ऐसे ढूँढ रहे थे मानो दूरबीन लगाकर कोई खोया हुआ खजाना खोजा जा रहा हो। जुबानी तीर चलने ही वाले थे कि अचानक बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल ने अपनी टेबल से सीधे सपा के टेंट में मुस्कुराते हुए चाय और पकौड़ी का पार्सल भिजवा दिया। उधर सपा खेमे में बैठे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा, नफीस अहमद अंसारी और अन्य दिग्गज नेता जब अपनी चुनावी गणित सुलझा रहे थे, तभी उनके सामने प्लेट में गरमा-गरम



पकौड़ियाँ आ गईं। पहले तो सपा नेता चौंके ये क्या है बीजेपी के टेंट से हमला हुआ है क्या लेकिन जवाब मिला नेताजी, ये हमला नहीं, 'स्वाद की संधि' है! फिर क्या था जो नेता एक-दूसरे के खिलाफ तीखे भाषण तैयार कर रहे थे, वे चाय की चुस्कियाँ और पकौड़ी के बाइट लेते हुए ठहाके लगाने लगे। शायद उनके मन में भी यही ख्याल आया होगा पार्टी का सिंबल भले ही 'कमल' हो या 'साइकिल' पर चाय के साथ पकौड़ी का सिंबल तो एवरग्रीन है! जहाँ कूटनीति के वैश्विक मंचों पर रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं रुक पा रहा, वहीं पीलीभीत में पकौड़ी ने दो धुर विरोधियों की कड़वाहट एक झटके में मिटा दी।

जब चाय पकौड़ी का यह अनूठा 'गठबंधन' हो ही गया, तो जनता यह पूछ रही है कि चटनी हरी वाली थी या मीठी क्योंकि पूरे माहौल में मिठास तो खुलकर घुल चुकी थी!

शहर का आम वोटर हैरान परेशान असमंजस में है कि अरे भाई! चुनाव लड़ रहे हो या 'मास्टरशेफ़ हम वोट देने जाएँ या इन नेताओं की चाय-पार्टी का बिल चुकाएँ इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और सच उजागर करने वाला पहलू यह है कि दोनों खेमों के आम कार्यकर्ता अब खामोश और हैरान हैं।

आगामी विधानसभा चुनाव सामने देखकर कार्यकर्ता मन ही मन सोच रहे हैं हम तो सड़कों पर उतरकर बेवजह एक-दूसरे से दुश्मनी मोल ले रहे हैं और आपसी रिश्ते खराब कर रहे हैं, जबकि ऊपर बैठकर हमारे नेता तो सब एक हैं!"

राजनीति भले ही आम जनता का दिल और दिमाग जलाती हो, लेकिन पीलीभीत की इस 'चाय-पकौड़ी डिप्लोमेसी' ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, दल बदलते रहेंगे, लेकिन जब बात आपसी सहूलियत की आएगी, तो भारतीय राजनीति का हर विरोध पानी-पानी होकर चाय में मिल जाएगा!

अब फैसला जनता के हाथ में है कि वह इस 'चुनावी चाय-पार्टी' को किस नजरिए से देखती है!

उद्योग केन्द्र का अवेयरनेस कैंप



परिवहन विशेष न्यूज

खूंटी। जिला उद्योग केंद्र, खूंटी के द्वारा एक दिवसीय अवेयरनेस कैंप उद्यम रजिस्ट्रेशन का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं तथा पुरुषों को जिला उद्योग केंद्र के EODB मैनेजर ने सभी को उद्योग से संबंधित स्व रोजगार के बारे में जानकारी दी। किरण लता भेंगरा ने मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड से पीएमएफएमई और पीएमईजीपी योजना के बारे में जानकारी दी। प्रभावती Jss से मार्केट लिंकेज के बारे में जानकारी दी। बिशेश्वर सिंह झारक्राफ्ट से भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन की विस्तृत जानकारी दी गई इस कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के EODB अभिनव राज, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग विकास बोर्ड से किरण लता भेंगरा, JIIT अकेडमी से बिरेंद्र नाग एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल थे।

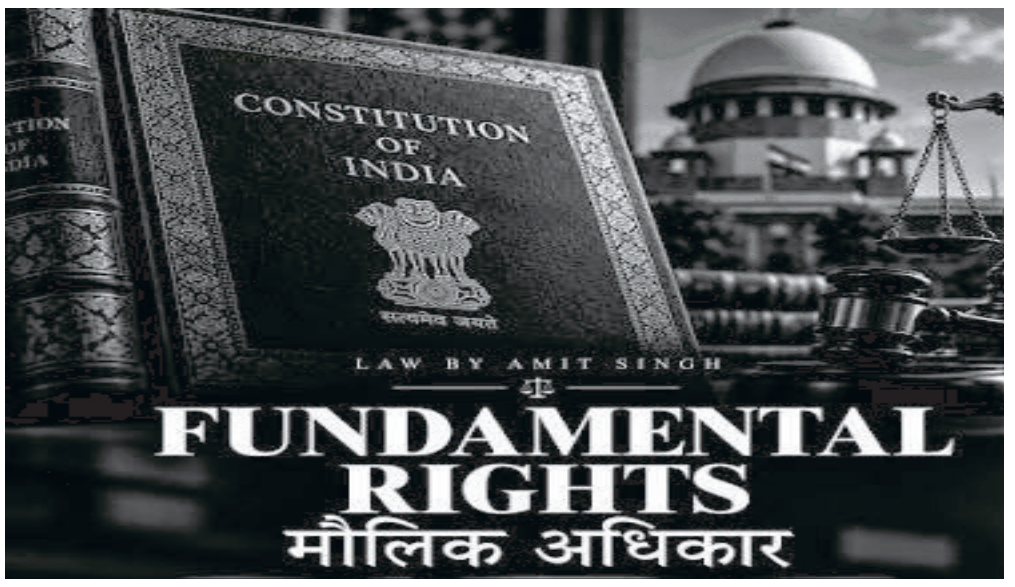
अंतरात्मा का आईना: विशेषाधिकार अधिकार नहीं, जिम्मेदारी हैं





● डॉ. विजय गर्ग

विशेषाधिकार का अर्थ केवल अपार धन-संपत्ति या ऊँचा पद प्राप्त करना नहीं है। अच्छी शिक्षा, सहयोगी परिवार, सुरक्षित घर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर भी विशेष सुविधाओं के रूप हैं। कुछ लोगों को ये सुविधाएँ परिस्थितियों के कारण मिल जाती हैं, जबकि दूसरे लोग अपनी मेहनत से अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाते हैं।



हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें अपनी संपत्ति, शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यावसायिक उपलब्धियों या प्रभाव के कारण विशेष सुविधाएँ और अवसर प्राप्त होते हैं। ये विशेषाधिकार जीवन के अनेक दरवाजे खोल सकते हैं, नए अवसर पैदा कर सकते हैं और जीवन को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं। लेकिन एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है: हम इन सुविधाओं का उपयोग किस प्रकार करते हैं? क्या हम इनका इस्तेमाल केवल अपने सुख-सुविधाओं के लिए करते हैं या कम अवसर प्राप्त करने वाले लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं?

अंतरात्मा का आईना हमें अपनी उपलब्धियों से आगे बढ़कर अपने चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि विशेषाधिकारों से अहंकार, श्रेष्ठता की भावना और अधिकार जताने की प्रवृत्ति पैदा होने के बजाय कृतज्ञता, विनम्रता और सेवा की भावना विकसित होनी चाहिए।

विशेषाधिकार का वास्तविक अर्थ

विशेषाधिकार का अर्थ केवल अपार धन-संपत्ति या ऊँचा पद प्राप्त करना नहीं है। अच्छी शिक्षा, सहयोगी परिवार, सुरक्षित घर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर भी विशेष सुविधाओं के रूप हैं। कुछ लोगों को ये सुविधाएँ परिस्थितियों के कारण मिल जाती हैं, जबकि दूसरे लोग अपनी मेहनत से अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाते हैं।

समस्या तब शुरू होती है, जब लोग अपनी सुविधाओं को अपनी अंतर्निहित श्रेष्ठता का प्रमाण मानने लगते हैं। संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी सफलता का पूरा श्रेय स्वयं को दे सकता है और उन अवसरों तथा सहयोग को भूल सकता है, जिन्होंने उसकी प्रगति में योगदान दिया। इसी प्रकार, शक्तिशाली पद पर बैठा व्यक्ति विशेष व्यवहार को अपना स्वाभाविक अधिकार समझने लगता है।

ऐसी सोच धीरे-धीरे संवेदनशीलता को कमजोर करती है और समाज में असमानता तथा दूरी बढ़ाती है।

विशेषाधिकार के साथ जिम्मेदारी आवश्यक

विशेषाधिकार तभी सार्थक बनते हैं, जब उनके साथ कर्तव्य की भावना भी जुड़ी हो। शिक्षा को विवेकपूर्ण सोच और सामाजिक जागरूकता विकसित करनी चाहिए। धन का उपयोग दूसरों के लिए अवसर पैदा करने में होना चाहिए। अधिकारों का उद्देश्य न्याय और निष्पक्षता की रक्षा करना होना चाहिए। व्यावसायिक सफलता दूसरों को मार्गदर्शन देने और ज्ञान साझा करने की प्रेरणा बननी चाहिए।

ज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना है। डॉक्टर अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से संवेदनशील चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान दे सकता है। प्रभावशाली नागरिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकता है, जबकि सफल उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा करके समाज के विकास में सहायता कर सकता है।

इन कार्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना आवश्यक नहीं है। बल्कि यह समझना जरूरी है कि व्यक्तिगत सफलता और सामूहिक कल्याण एक-दूसरे को मजबूत बना सकते हैं।

समाज तब प्रगति करता है, जब सफल लोग दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, न कि अपनी सुविधाओं और प्रतिष्ठा के कारण उनसे दूरी बनाए रखते हैं।

अधिकार जताने की मानसिकता का खतरा

जब लोग अपने पद, संपत्ति, पारिवारिक संबंधों या सामाजिक पहचान के कारण विशेष व्यवहार को अपना अधिकार समझने लगते हैं, तो उनमें अनुचित अपेक्षाएँ विकसित होने लगती हैं। इसका उदाहरण रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देता है—दूसरों को अनावश्यक प्रतीक्षा करवाना, नियमों की अनदेखी करना, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, अनुचित सिफारिशें माँगना या कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करना।

जब विशेषाधिकार अधिकार जताने का साधन बन जाते हैं, तो जवाबदेही कमजोर पड़ने लगती है। लोग सहयोग के बजाय आज्ञाकारिता और सम्मान अर्जित करने के बजाय प्रशंसा की अपेक्षा करने लगते हैं।

यह प्रवृत्ति सार्वजनिक संस्थाओं में विशेष रूप से हानिकारक है। अधिकार वाले पद जनता की सेवा के लिए होते हैं, व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं या असीमित शक्ति के लिए नहीं। सार्वजनिक पद एक विश्वास और जिम्मेदारी है, निजी संपत्ति नहीं। इसी प्रकार, शैक्षणिक योग्यताओं और व्यावसायिक पदों का उद्देश्य योग्यता, ईमानदारी और नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करना होना चाहिए, न कि दूसरों पर श्रेष्ठता जताना।

किसी व्यक्ति के चरित्र की वास्तविक पहचान इस बात से नहीं होती कि कितने लोग उसकी सेवा करते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि वह उन लोगों के साथ कितना सम्मानपूर्ण व्यवहार करता है, जिनसे उसे कोई व्यक्तिगत लाभ मिलने की अपेक्षा नहीं होती।

परिवार और शिक्षा की भूमिका

विशेषाधिकारों से जुड़ी मानसिकता और मूल्य अक्सर बचपन में ही विकसित होने लगते हैं। सुख-सुविधाओं में पलने वाले बच्चों को कृतज्ञता, सहानुभूति, अनुशासन और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों का सम्मान करना भी सिखाया जाना चाहिए।

माता-पिता बच्चों को घरेलू सहायकों की मेहनत का सम्मान करने, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखने, संसाधनों को साझा करने और वंचित समुदायों की कठिनाइयों को समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

शैक्षणिक संस्थानों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाओं में सफलता, रोजगार और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य ऐसे जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी है, जो समानता, न्याय, सहयोग और सामाजिक कर्तव्यों को समझते हों।

समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, स्वैच्छिक कार्य और वंचित वर्गों के लोगों के साथ संवाद युवाओं को यह समझने में सहायता करते हैं कि समाज की प्रगति पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है।

अपने भीतर झाँकने का समय

वास्तविक परिवर्तन ईमानदार आत्ममंथन से शुरू होता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए: क्या मैं अपने पद और अधिकारों का निष्पक्ष उपयोग करता हूँ? क्या मैं सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता हूँ? क्या मैं अपनी सफलता में दूसरों के योगदान को स्वीकार करता हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए अवसर पैदा करने में सहायता करता हूँ? क्या मैं आलोचना स्वीकार करके अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहता हूँ?

इन प्रश्नों का उद्देश्य किसी को सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए दोषी महसूस कराना नहीं है, बल्कि अपनी सुविधाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है।

विशेषाधिकार अपने आप में कोई नैतिक दोष नहीं हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि वे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार होता है और उन्हें दूसरों के हित में किस सीमा तक साझा किया जाता है। कुछ सुविधाएँ कठिन परिश्रम से प्राप्त होती हैं, जबकि कुछ असमान सामाजिक व्यवस्थाओं या जन्म की परिस्थितियों के कारण मिलती हैं। इन अंतरों को समझने से हम अपनी उपलब्धियों की सराहना करने के साथ-साथ दूसरों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील भी बनते हैं।

अधिक जिम्मेदार समाज का निर्माण

एक न्यायपूर्ण समाज के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी लोगों के पास समान संसाधन हों या वे बिल्कुल एक जैसा जीवन जिएँ। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, निष्पक्ष अवसर, जवाबदेह संस्थाएँ और मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए।

सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक सेवाएँ जरूरतमंद लोगों तक पहुँचें। संस्थाओं को भेदभाव और अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और उपलब्ध अवसरों के अनुसार समाज के कल्याण में योगदान देना चाहिए।

किसी विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना, जरूरतमंद परिवार की सहायता करना, व्यावसायिक ज्ञान साझा करना, पर्यावरण की रक्षा करना या अनुचित कार्यों में भाग लेने से इनकार करना—ये छोटे कदम भी सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं।

अंततः, अंतरात्मा का आईना हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाता है, जिसे धन, प्रतिष्ठा और शक्ति छिपा नहीं सकते: विशेषाधिकारों का वास्तविक मूल्य उनके जिम्मेदार उपयोग में निहित है।

विशेषाधिकार श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर हैं। जब सुविधाएँ अधिकार जताने के बजाय सेवा की प्रेरणा बनती हैं, तो सफलता अधिक सार्थक, नेतृत्व अधिक मानवीय और समाज अधिक न्यायपूर्ण बनता है। असली प्रश्न केवल यह नहीं है कि विशेषाधिकारों से हमें क्या मिला, बल्कि यह भी है कि उनके माध्यम से हमने समाज को क्या लौटाया।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। शैक्षिक स्तंभकार। प्रख्यात शिक्षाविद् स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब – 152107

सौंदर्य की वैज्ञानिक समझ

डॉ. विजय गर्ग

सौंदर्य मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम प्रकृति के रंगों, इमारतों की बनावट, वस्तुओं की सजावट, फूलों के आकार और संगीत की मधुरता में सौंदर्य का अनुभव करते हैं। यद्यपि सौंदर्य को अक्सर व्यक्तिगत पसंद का विषय माना जाता है, लेकिन विज्ञान बताता है कि सौंदर्य के प्रति हमारी धारणा गणितीय प्रतिरूपों, जैविक प्रतिक्रियाओं, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक अनुभवों से भी प्रभावित होती है। वस्तुओं और वास्तुकला के बीच संबंध को समझना सौंदर्य के विज्ञान को जानने का एक रोचक माध्यम है।

बाहरी रूप से परे सौंदर्य

सौंदर्य केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है। इसमें संतुलन, अनुपात, समरूपता, सामंजस्य, उपयोगिता और विभिन्न तत्वों के बीच संबंध भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, किसी सुंदर इमारत के निर्माण में महँगी सामग्री या भव्य सजावट का होना आवश्यक नहीं है। उसकी सुंदरता स्थान के विवेकपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक प्रकाश, उचित वायु-संचार, संतुलित अनुपात और आसपास के वातावरण के साथ उसके तालमेल में निहित हो सकती है।

इसी प्रकार, एक साधारण वस्तु भी अपने आकार, रंग, बनावट और उपयोगिता के मेल से आकर्षक बन सकती है। अच्छी तरह बनाई गई कुर्सी, मिट्टी का साधारण घड़ा या सुव्यवस्थित अध्ययन-मेज यह दर्शाती है कि सादगी और विचारपूर्ण डिजाइन से भी सुंदरता उत्पन्न हो सकती है।

इस प्रकार, सौंदर्य का वैज्ञानिक अध्ययन हमें केवल बाहरी रूप देखने के बजाय उन सिद्धांतों को समझने के लिए प्रेरित करता है, जो किसी वस्तु को आकर्षक, उपयोगी और अर्थपूर्ण बनाते हैं।

सौंदर्य का गणित

सौंदर्य की अनुभूति में गणित की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। समरूपता, अनुपात, प्रतिरूप और ज्यामितीय संबंध प्रकृति तथा मानव-निर्मित संरचनाओं में व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। सूरजमुखी के बीजों की सर्पिल व्यवस्था, पेड़ों की शाखाओं का फैलाव, समुद्री शंखों के आकार और अनेक फूलों की समरूपता दर्शाती है कि गणितीय सिद्धांत प्राकृतिक आकृतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

वास्तुकला में अनुपात दृश्य संतुलन उत्पन्न करने में सहायक होता है। किसी भवन की ऊँचाई और चौड़ाई का संबंध, खिड़कियों के बीच की दूरी, स्तंभों की व्यवस्था तथा प्रवेश-द्वार की बनावट यह प्रभावित कर सकती है कि लोग उस संरचना को किस प्रकार देखते हैं। ज्यामितीय प्रतिरूप और दोहराए गए आकार व्यवस्था तथा एकरूपता का अनुभव कराते हैं।

कलात्मक और वास्तुशिल्पीय सौंदर्य के संदर्भ में स्वर्ण अनुपात (Golden Ratio) की अक्सर चर्चा होती है। यद्यपि इसका उपयोग विभिन्न डिजाइनों में हुआ है, फिर भी इसे सौंदर्य का सार्वभौमिक सूत्र नहीं माना जाना चाहिए। मनुष्यों की पसंद अलग-अलग होती है और आकर्षक डिजाइन अनेक प्रकार के अनुपातों पर आधारित हो सकते हैं।

मुख्य बात यह है कि गणितीय व्यवस्था सौंदर्य में योगदान दे सकती है, लेकिन सौंदर्य को किसी एक समीकरण तक सीमित नहीं किया जा सकता।

वस्तुएँ और वास्तुकला: एक-दूसरे से जुड़ा संबंध

वस्तुएँ और वास्तुकला एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। वस्तुएँ स्थान घेरती हैं, जबकि वास्तुकला वह परिवेश प्रदान करती है, जिसमें उनका उपयोग किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है और उनका अनुभव किया जाता है। इनका पारस्परिक संबंध किसी स्थान की समग्र सुंदरता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है।

एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए, जिसमें उचित फर्नीचर, एक-दूसरे से मेल खाते रंग, पर्याप्त प्रकाश और खुली जगह हो। प्रत्येक वस्तु अपने आप में सुंदर हो सकती है, लेकिन कमरा तब अधिक आकर्षक बनता है, जब उसकी सभी वस्तुएँ एक-दूसरे के अनुकूल हों। इसके विपरीत, अत्यधिक सजावटी वस्तुएँ, परस्पर विरोधी रंग या अव्यवस्थित फर्नीचर दृश्य भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं।

इस संबंध को वस्तु-वास्तु समीकरण कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि किसी स्थान की सुंदरता केवल उसके अलग-अलग घटकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे घटक एक-दूसरे के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हैं।

यह समीकरण कोई निश्चित गणितीय सूत्र नहीं, बल्कि एक वैचारिक अवधारणा है। यह सुंदर परिवेश बनाने में तालमेल, अनुपात, उपयोगिता और संदर्भ के महत्त्व को रेखांकित करती है।

सौंदर्य का मनोविज्ञान

मानवीय अनुभूति यह निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हमें क्या सुंदर दिखाई देता है। मनोविज्ञान संबंधी शोध बताते हैं कि लोग अक्सर दृश्य स्पष्टता, परिचित प्रतिरूपों, संतुलित संरचनाओं और कुछ प्रकार की समरूपता को पसंद करते हैं। हालांकि, व्यक्तिगत पसंद अनुभवों, भावनाओं, परवरिश और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होती है।

पंजाब का पारंपरिक आँगन किसी व्यक्ति के मन में अपनत्व और पुरानी यादों को जागृत कर सकता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को आधुनिक और न्यूनतम सजावट वाला घर अपनी सादगी के कारण आकर्षित कर सकता है। दोनों सुंदर हो सकते हैं, क्योंकि सौंदर्य में केवल भौतिक संरचना ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक अर्थ भी शामिल होते हैं।

रंग भी सौंदर्य का एक महत्त्वपूर्ण तत्व हैं। हल्के और सौम्य रंग शांति का अनुभव करा सकते हैं, जबकि विपरीत रंग ध्यान आकर्षित करते हैं और ऊर्जा का संकेत देते हैं। प्रकाश रंगों, बनावट और आकृतियों को देखने के तरीके को प्रभावित करता है। प्राकृतिक प्रकाश किसी स्थान को खुला और स्वागतपूर्ण बना सकता है, जबकि अनुचित प्रकाश उसकी दृश्य सुंदरता को कम कर सकता है।

इस प्रकार, सौंदर्य भौतिक परिवेश और मानवीय मन के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होता है।

प्रकृति: डिजाइन की शिक्षक

प्रकृति वास्तुकारों, कलाकारों और डिजाइनरों के लिए अनेक उपयोगी सीख प्रस्तुत करती है। पेड़ संरचना और स्थिरता के संबंध को समझाते हैं। फूल रंगों और समरूपता की अभिव्यक्ति दिखाते हैं। पर्वत विशालता की सुंदरता प्रस्तुत करते हैं, जबकि नदियाँ और प्राकृतिक दृश्य बताते हैं कि अनियमित आकृतियों में भी सामंजस्य हो सकता है।

प्राकृतिक सुंदरता हमेशा सममित नहीं होती। बादल, ऊबड़-खाबड़ पर्वत, बहती नदियाँ और समय के साथ घिसे हुए पत्थर अपनी अनियमितता के कारण भी विशिष्ट आकर्षण रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्णता का अर्थ हमेशा एकरूपता नहीं होता।

आधुनिक वास्तुकला में प्राकृतिक प्रकाश, हरियाली, प्राकृतिक सामग्री और ऊर्जा-कुशल डिजाइन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे तरीके इमारतों की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ आराम और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक हो सकते हैं। सौंदर्य अधिक सार्थक तब बनता है, जब वह प्रकृति के विरुद्ध जाने के बजाय उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है।

उपयोगिता और स्थिरता

किसी सुंदर वस्तु या भवन को आदर्श रूप से अपना उद्देश्य भी प्रभावी ढंग से पूरा करना चाहिए। देखने में आकर्षक लेकिन असुविधाजनक कुर्सी का डिजाइन अधूरा है। इसी प्रकार, ऐसी भव्य इमारत जो ऊर्जा की बर्बादी करे, प्राकृतिक प्रकाश को रोके या दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की अनदेखी करे, वह मानवीय जरूरतों को पूरा करने में असफल हो सकती है।

अच्छा डिजाइन सौंदर्य और उपयोगिता को एक साथ जोड़ता है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। यह उपलब्ध स्थान का कुशल उपयोग करता है, अनावश्यक अपव्यय को कम करता है और टिकाऊ निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

इसी प्रकार, टिकाऊ सामग्री का चयन, उपयोगी वस्तुओं की मरम्मत और अनावश्यक सजावट से बचाव पर्यावरणीय जिम्मेदारी तथा सादगीपूर्ण सौंदर्य, दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं।

इस अर्थ में, सौंदर्य केवल देखने की वस्तु नहीं है, बल्कि आराम, उपयोगिता और सामंजस्य के माध्यम से अनुभव की जाने वाली भावना भी है।

क्या सौंदर्य को मापा जा सकता है?

विज्ञान सौंदर्य से जुड़ी कई विशेषताओं को माप सकता है। इनमें समरूपता, अनुपात, रंगों का विरोधाभास, प्रकाश का स्तर और स्थानिक संबंध शामिल हैं। शोधकर्ता सर्वेक्षणों, प्रयोगों और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास भी करते हैं कि लोग विभिन्न डिजाइनों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

हालाँकि, कोई भी वैज्ञानिक उपकरण प्रत्येक सुंदर वस्तु या भवन से जुड़े भावनात्मक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व को पूरी तरह नहीं माप सकता। एक ही संरचना को देखकर दो व्यक्ति बिल्कुल अलग-अलग भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं।

इसलिए सौंदर्य आंशिक रूप से मापने योग्य और आंशिक रूप से व्यक्तिपरक है। वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाने में सहायता करते हैं कि कुछ डिजाइन अनेक लोगों को आकर्षक क्यों लगते हैं, लेकिन वे मानवीय पसंद की विविधता को समाप्त नहीं कर सकते।



वस्तुएँ और वास्तुकला एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। वस्तुएँ स्थान घेरती हैं, जबकि वास्तुकला वह परिवेश प्रदान करती है, जिसमें उनका उपयोग किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है और उनका अनुभव किया जाता है। इनका पारस्परिक संबंध किसी स्थान की समग्र सुंदरता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए, जिसमें उचित फर्नीचर, एक-दूसरे से मेल खाते रंग, पर्याप्त प्रकाश और खुली जगह हो। प्रत्येक वस्तु अपने आप में सुंदर हो सकती है, लेकिन कमरा तब अधिक आकर्षक बनता है, जब उसकी सभी वस्तुएँ एक-दूसरे के अनुकूल हों। इसके विपरीत, अत्यधिक सजावटी वस्तुएँ, परस्पर विरोधी रंग या अव्यवस्थित फर्नीचर दृश्य भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। इस संबंध को वस्तु-वास्तु समीकरण कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि किसी स्थान की सुंदरता केवल उसके अलग-अलग घटकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे घटक एक-दूसरे के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हैं।

निष्कर्ष

सौंदर्य की वैज्ञानिक समझ वस्तुओं, वास्तुकला, गणित, मनोविज्ञान और प्रकृति के बीच एक रोचक संबंध को उजागर करती है। आकर्षक परिवेश सामान्यतः किसी एक विशेषता का परिणाम नहीं होता। यह अनुपात, रंग, बनावट, प्रकाश, उपयोगिता और मानवीय अनुभव के विचारपूर्ण तालमेल से उत्पन्न होता है।

वस्तु-वास्तु का समीकरण हमें सिखाता है कि सुंदरता केवल अलग-अलग वस्तुओं में ही नहीं, बल्कि उनके पारस्परिक संबंधों में भी निहित होती है। सुव्यवस्थित स्थान में सोच-समझकर रखी गई एक साधारण वस्तु, बिना उद्देश्य की महँगी सजावट की तुलना में अधिक सामंजस्य उत्पन्न कर सकती है।

अंततः, सौंदर्य का विज्ञान हमें बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ डिजाइन करने की प्रेरणा देता है। जब सौंदर्य का मेल उपयोगिता, पर्यावरणीय स्थिरता और मानवीय मूल्यों से होता है, तब वह केवल आँखों को अच्छा लगने वाला अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि संतुलित और विचारशील जीवनशैली की अभिव्यक्ति बन जाता है।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य। प्रख्यात वैज्ञानिक स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब – 152107

लमलोई बायपास राजगांगपुर की बुझी हाईमास्ट लाइट पर प्रशासन मौन

दस वर्षों से खड़ी है शोपीस बनी हाईमास्ट; नगर पालिका, ब्लॉक और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल



रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राजगांगपुर।

राजगांगपुर के लमलोई बायपास चौक पर लगी हाईमास्ट लाइट इन दिनों प्रशासनिक उदासीनता और विकास कार्यों में बरती गई लापरवाही का प्रतीक बनकर रह गई है। ओआईएसएल स्पॉंज के सामने और सजन जी पेट्रोल पंप के समीप स्थित यह चौक अत्यंत व्यस्त मार्ग पर है। यहां जटिल मोड़, भारी यातायात और लगातार आवागमन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद रात के समय पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहता है।

जानकारी के अनुसार, राजगांगपुर ब्लॉक के अंतर्गत लगभग दस वर्ष पहले इस हाईमास्ट लाइट को स्थापित किया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण और स्थापना के समय अधिकारियों तथा संबंधित ठेकेदारों ने केवल औपचारिकता पूरी की। कमीशनखोरी के आरोपों के बीच लगाई गई यह लाइट आज तक नियमित रूप से एक वर्ष भी ठीक से नहीं जल पाई। करोड़ों रुपये की योजनाओं और उद्घाटनों का दावा करने वाले विभाग इस बुनियादी सुविधा की सुध लेने को तैयार नहीं हैं।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका चुनाव के समय कुछ दिनों के लिए हाईमास्ट लाइट जलाई गई थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती है। चुनाव समाप्त होते ही लाइट फिर बंद हो गई। इससे प्रशासन की प्राथमिकताओं और जनसुरक्षा के प्रति उसकी गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं।

इस मार्ग से जिलापाल, विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि नियमित रूप से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इस बदहाल व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका, राजगांगपुर ब्लॉक और जिला प्रशासन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हाईमास्ट लाइट की तत्काल तकनीकी जांच कराकर उसे स्थायी रूप से चालू किया जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। प्रशासन यदि अब भी नहीं जागा, तो किसी बड़े हादसे के बाद ही उसकी नींद टूटेगी।



गोविंदपुर सीएचसी की कार्यशैली पर सवाल, मरीजों की परेशानी के बीच अधिकारियों की चुप्पी!

निजी प्रैक्टिस को लेकर चिकित्सक पी. मिश्रा के कथित बयान से बढ़ा विवाद, सीडीएमओ से संपर्क पर भी नहीं मिला स्पष्ट जवाब

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र

बामड़ा। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य आम जनता को समय पर और सुलभ उपचार उपलब्ध कराना है, लेकिन जब सरकारी अस्पताल पहुंचने पर मरीजों को चिकित्सक की अनुपलब्धता की शिकायत करनी पड़े, तो व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना लाजिमी है। बामड़ा क्षेत्र के गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें अब गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। आरोप है कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को कई बार चिकित्सक पी. मिश्रा के निजी क्लीनिक में होने की जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि गरीब और ग्रामीण मरीजों को इलाज के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। शिकायतों में संबंधित चिकित्सक के निजी क्लीनिक और उनके पिता द्वारा संचालित दवा दुकान का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस संबंध में किसी अनुचित सांठगांठ की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

'जहां जाना है जाइए'— कथित बयान से बढ़ा विवाद इस मामले में चिकित्सक पी. मिश्रा की कथित प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी हुई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा, "आपको जहां जाना है, आप जाइए। मैं अपनी इच्छा से, जहां इच्छा हो, वहां प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र हूं।" यदि यह बयान इसी संदर्भ में दिया गया है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकारी सेवा से जुड़ी जिम्मेदारियों और निजी प्रैक्टिस के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। संबंधित चिकित्सक का पक्ष स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जाना भी आवश्यक है।

सीडीएमओ से बातचीत भी बेनतीजा मामले पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) से भी संपर्क किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, पूरी बात रखने के बाद जब उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने फोन पर आवाज स्पष्ट नहीं होने की बात कही और कॉल समाप्त कर दी। इस बातचीत से शिकायतकर्ता को कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला। हालांकि, इस आधार पर अधिकारी की मंशा पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

अब सवाल यह है कि सरकारी अस्पताल में चिकित्सक की उपस्थिति, निजी प्रैक्टिस से जुड़े नियमों और मरीजों की शिकायतों की जांच कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग को उपस्थिति रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर और संबंधित तथ्यों की जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर आम मरीजों को राहत कब मिलेगी और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा?

जिले में प्रदूषण कम था, जो बाहर से भी फ्लाई ऐश लाकर डाली जा रही है?

कुआरमुंडा में फ्लाई ऐश डंपिंग पर प्रशासनिक पत्राचार, कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने का आरोप

तहसीलदार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी जांच और कार्रवाई; आदर्श विद्यालय परिसर में फ्लाई ऐश भराव को लेकर भी उठे गंभीर सवाल, जिलापाल और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र सुंदरगढ़।

जिले में औद्योगिक प्रदूषण की समस्या के बीच अब दूसरे क्षेत्रों से फ्लाई ऐश लाकर डंप किए जाने का मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कुआरमुंडा और कुमझरिया क्षेत्र में कथित फ्लाई ऐश डंपिंग को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पत्राचार होने के बावजूद निर्णायक कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता डॉ. राजकुमार यादव ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, पानपोष के तहसीलदार ने 9 जुलाई 2026 को कुआरमुंडा मौजा में लगभग 24,000 घनमीटर फ्लाई ऐश डंप किए जाने के आरोप पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राउरकेला को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद 8 सितंबर 2026 को कुमझरिया राजस्व निरीक्षक क्षेत्र में फ्लाई ऐश डंपिंग के संबंध में भी बोर्ड से कार्रवाई तथा कानून के अनुसार जुर्माना लगाने का अनुरोध किया गया। पत्र में विभिन्न भूखंडों पर फ्लाई ऐश और मिट्टी-मिश्रित फ्लाई ऐश डाले जाने का विवरण भी संलग्न है।

मामले का दूसरा गंभीर पहलू कुआरमुंडा स्थित ओडिशा आदर्श विद्यालय परिसर से जुड़ा है। तहसीलदार की 8 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय परिसर की जमीन के एक हिस्से पर फ्लाई ऐश डालकर ऊपर मिट्टी बिछाई गई थी। रिपोर्ट में विद्यालय के प्राचार्य के हवाले से कहा गया कि भराव कार्य के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति उपलब्ध है। संलग्न सहमति आदेश में 1,28,690 घनमीटर फ्लाई ऐश के निस्तारण का उल्लेख है। हालांकि, इस अनुमति की शर्तों के पालन, वास्तविक स्थल, परिवहन स्रोत और पर्यावरणीय प्रभाव की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्थानीय प्रशासन स्वयं संभावित पर्यावरणीय नुकसान को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्रवाई मांग रहा है, तो जमीन पर प्रभावी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित क्यों नहीं हो रही? क्या सुंदरगढ़ जिले में प्रदूषण की समस्या कम थी कि दूसरे क्षेत्रों से भी फ्लाई ऐश लाकर यहां डंप की जा रही है? यदि परिवहन और निस्तारण नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी?

डॉ. राजकुमार यादव ने जिलापाल, सुंदरगढ़ और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, फ्लाई ऐश के स्रोत और परिवहन मार्ग की पहचान, अनुमति की शर्तों के सत्यापन तथा प्रभावित मिट्टी, पानी और हवा की वैज्ञानिक जांच कराने की अपील की है।

यह मामला केवल जमीन पर राख डालने का नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, ग्रामीणों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के भविष्य का है। प्रशासनिक पत्राचार के बीच यदि जिम्मेदारी एक विभाग से दूसरे विभाग तक ही घूमती रही, तो आम जनता का भरोसा कमजोर होगा। अब आवश्यकता आश्वासनों की नहीं, बल्कि समयबद्ध जांच, पारदर्शी रिपोर्ट और ठोस कार्रवाई की है।



सिंहासन खाली करो कि जनता आती है! (आलेख : राजेंद्र शर्मा)

बिहार में चुनाव के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामधारी सिंह दिनकर को याद करना नहीं भूलते हैं। लेकिन, लगता है कि इस महान कवि की उक्त कालजयी पंक्ति को समझ कर भी नासमझ बनने की मुद्रा अपनाने में ही प्रधानमंत्री ने अपना फायदा समझा है। वर्ना पिछले करीब हफ्ते भर से सत्ताधारी निजाम जिस तरह से अपने हटाए जाने की देसी ही नहीं, विदेशी तक साजिशों का सरासर झूठा शोर मचाकर, अपने राज में रचे गए चुनावों को ही बेमानी बना देने के संविधानविरोधी, जनतंत्रविरोधी षडयंत्र पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, उसने दिनकर की उक्त पंक्ति को कब का राष्ट्र-विरोधी घोषित कर दिया होता। क्योंकि कवि ने जनता की इच्छा के लिए, सिंहासन खाली करने की बात तो कही है, लेकिन इसमें साफ-साफ शब्दों में यह शर्त तो जोड़ी ही नहीं है कि चुनाव के जरिए जनता (की इच्छा) आती है!

यह और भी विडंबनापूर्ण है कि अपने विरोधियों और आलोचकों पर, चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन के जनतांत्रिक तरीके के बजाए, अलोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता परिवर्तन का षडयंत्र रचने के आरोप, वही सत्ताधारी संघ-भाजपा गिरोह लगा रहा है, जिस पर इल्जाम ही यह है कि उसने पूरी तरह से पक्षपाती चुनाव आयोग के साथ मिलकर, ठीक चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन का रास्ता ही रोकने का षडयंत्र रचा है। दूसरे शब्दों में, सत्ताधारियों का विपक्ष पर अलोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता परिवर्तन की कोशिश का आरोप, वास्तव में देश में चुनाव को ही निरर्थक बना देने के मौजूदा निजाम के इंतजामों का ही पूरक है। सत्ताधारियों को चिंता है कि इसका इंतजाम तो उन्होंने कर लिया है कि चुनाव के जरिए उन्हें सत्ता से हटाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन यह भी 'जनता के आ धमकने' से तो पूर्ण सुरक्षा नहीं देता है। तानाशाहों को जनता के आने के खिलाफ सुरक्षा के लिए हमेशा राजकीय हिंसा की जरूरत होती है और जनता से पूर्ण सुरक्षा के लिए, उसकी हरेक हरकत को, हरेक आंदोलन को आपराधिक षडयंत्र बना देने की।

अपने खिलाफ जनता के हरेक आंदोलन को, अपनी हरेक गंभीर आलोचना को, आपराधिक षडयंत्र बना देने में वर्तमान मोदी-शाह निजाम ने भारी महारत हासिल कर ली है। इस जनविरोधी और बुनियादी अर्थ में जनतंत्रविरोधी खेल के सिर्फ तीन खास उदाहरणों की यहां याद दिलाना ही काफी होगा। इसका पहला उदाहरण, भीमा कोरेगांव षडयंत्र केस है, जिसमें एक मुख्यतः दलित गोलबंदी पर, सवर्ण हिंदुत्ववादी गिरोहों की पूरी तरह से अकारण हिंसा का बचाव करने के





लिए, इसे शासन को पलटने के तथा प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के षडयंत्र में बदल दिया गया। दूसरा उदाहरण, तीन काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसे ''खालिस्तानी आतंकवाद'' से लेकर, विदेशी टूलकिट तक, न जाने किस-किस के षडयंत्र की उपज बताने की कोशिश की गयी थी। तीसरा उदाहरण, तथाकथित दिल्ली दंगा वृहत्तर षडयंत्र केस है, जिसके जरिए भारतीय नागरिकता की परिभाषा में एक सरासर अन्यायपूर्ण व असंवैधानिक, सांप्रदायिक बदलाव के खिलाफ आम जनता और विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुसलमानों के विरोध को, षडयंत्र साबित करने में शासन की पूरी ताकत लगा दी गयी है। बेशक, ऐसे ही उदाहरण और भी अनेक हैं, लेकिन यहां इन तीन उदाहरणों का जिक्र सिर्फ यह रेखांकित करने के लिए किया जा रहा है कि मोदी निजाम ने, अपने नियंत्रण से बाहर जनता की हरेक गोलबंदी को, राष्ट्रविरोधी षडयंत्र साबित करने कोशिश करने को नियम ही बना लिया है। और तो और, मोदी के सर्वाधिक कृपाप्राप्त, महा-धन्नासेठ, अडानी की कारोबारी धांधलियों और गड़बडियों को उजागर किए जाने को भी वर्तमान निजाम ने हर बार, भारत-विरोधी षडयंत्र बनाने की ही कोशिश की है।

इसलिए, हैरानी की बात नहीं है कि नीट परीक्षा लीक के बहाने, शिक्षा की बहाली तथा रोजगार के अभाव की युवाओं की चिंताओं के गिर्द और कॉकरोच जनता पार्टी तथा वामपंथी छात्र संगठनों की पहल पर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को केंद्र में रखकर देश में विशेष कर युवाओं या जेन जी की गोलबंदी हुई थी, मोदी राज ने उसे भी अपने खिलाफ देशी-विदेशी षडयंत्र बनाने की और शासन की ताकत के बल पर दबाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। यह दूसरी बात है कि दमन के उसके ये हथकंडे उसके लिए उल्टे पड़ गए और उसके अपने मध्यवर्गीय समर्थन आधार में भी दरारें पडने लगीं, जिसे संभालने की कोशिश में उसे अपनी रहमारे राज में इस्तीफे नहीं होतेर की तानाशाहाना ठसक को छोडक़र, प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा।

लेकिन, तब तक खुल्लमखुल्ला सत्तापक्ष का पहरुआ बन गए चुनाव आयोग की मदद से, मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर मर्जी के नाम जोडने और नापसंद नाम काटने के जरिए, चुनावों को प्रभावित करने के खेल को, मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण या एसआईआर के जरिए, सत्ताधारियों के हिसाब से मतदाताओं की चुनाव के स्तर पर पहुंचा दिया और वह भी खुल्लमखुल्ला मनमानी करते हुए। बंगाल के चुनाव में यह खेल एकदम ही खुलकर सामने आ गया, जहां केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए, न सिर्फ समूची चुनावी मशीनरी तथा चुनावों के दौरान प्रशासनिक मशीनरी को ठोक-पीटकर केंद्रीय सत्ता के प्रति वफादार बना दिया गया बल्कि पूरे सत्ताईस लाख मतदाताओं का मताधिकार घोषित रूप से छीनते हुए, जोकि टार्गेटेड तरीके से किया जा रहा था, चुनाव कराए गए, जिसने चुनाव को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ये लाखों मतदाता चुनाव के महीनों बाद भी अनिश्चितता के झूले ही में झूल रहे हैं, जबकि बंगाल में चुनाव आयोग की मदद से कराए गए रिजीम चेंज या सत्ता परिवर्तन के बाद से, इनकी नागरिकता पर भी सवालिया निशान लगा दिए गए हैं।

इसी सब की पृष्ठांभूमि में, जब यह तथ्य सामने आया कि एसआइआर की प्रक्रिया में, जिससे अब भी देश का एक हिस्सा कवर नहीं हुआ है, पिछली मतदाता सूचियों में रहे पूरे 13 करोड़ 30 लाख नाम बाहर किए जा चुके हैं, जो कि दुनिया के आठ-दस सबसे बड़े देशों को छोडक़र, बाकी सभी देशों की आबादी से भी ज्यादा संख्या है, तो इस प्रक्रिया के साथ शुरूआत से ही लगा रहा ''वोट चोरी'' का संदेह यकीन में बदल गया और इसकी आलोचनाएं एक जन-विक्षोभ में। राजधानी दिल्ली में, जहां हर तीसरा मतदाता इसकी कैंची के नीचे आ गया और दो चुनाव आयुक्तों समेत, अनेक वीआइपी मतदाताओं का वोट खतरे में आ गया, जिनके लिए चुनाव आयोग को संबंधित एप में अलग से विशेष व्यवस्था भी करनी पड़ी और दूसरी ओर, कई मतदान केंद्रों पर करीब सारे के सारे वोट ही एसआइआर की कैंची के नीचे आ गए, मीडिया में अपेक्षाकृत अधिक तथा मतदाताओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण कवरेज ने इस विभीषिका को देश भर के सामने गहरे रंग से रेखांकित कर दिया।

इसी पृष्ठभूमि में आए इंडियन एक्सप्रेस तथा अन्य प्रकाशनों के रहस्योदघाटनों ने विपक्ष की बदतरीन आशंकाओं की सचाई के सबूत पेश कर दिए। अब यह साफ था कि मतदाता सूचियों में फेर-बदल की सारी प्रक्रिया, खुद चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं से भी स्वतंत्र, एक गुट-विशेष या कोटरी के ही हाथों में केंद्रित हो गयी थी, जो पूरी तरह से मनमाने तथा अपारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को संचालित कर रही थी। इसे खुद चुनाव आयुक्तों के बहुमत को किनारे कर के सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त की इच्छा से संचालित किया जा रहा था और इस व्यवस्था के तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े हुए थे। ईसीआइनेट के जिस कंप्यूटरी ताने-बाने के जरिए इस समूची प्रक्रिया को संचालित किया जा रहा था, उसका नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र के चंद खासुल खासों तक सीमित था। दूसरी ओर, जो ईआरओ कानूनन मतदाता सूचियों में नाम जोडने-हटाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इस प्रक्रिया में पूरी तरह से अधिकारहीन बना दिया गया था।

और मनमानी का आलम यह था कि बंगाल में, 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम, पूरी प्रक्रिया के बाद सूची से हटाने के लिए खुद चुनाव आयोग की ओर से अपीलें दायर की गयी थीं, जो केंद्र में कंप्यूटर-प्रणाली के जरिए और वास्तव में दो चुनाव आयुक्तों के अंधेरे में रखकर किया जा रहा था। बाद में उत्तराखंड आदि अन्य कई राज्यों में भी चुनाव आयोग के ''सिस्टम'' द्वारा ही फार्म 7 के जरिए मतदाताओं के नाम काटे जाने जानकारियां सामने आयीं। दूसरी ओर खासतौर पर भाजपा तथा संघ परिवार के विभिन्न बाजुओं द्वारा फार्म 7 के जरिए, थोक में उत्तराखंड से लेकर तेलंगाना व कर्नाटक तक, विरोधी या राजनीतिक रूप से संदिग्ध मतदाताओं के नाम कटवाए जाने और उत्तर प्रदेश तथा कई अन्य राज्यों से फार्म 6 के जरिए इसी तरह लाखों नाम जोड़े जाने के की खबरें भी सामने आयी हैं। कुल मिलाकर यह कि एसआइआर के जरिए चुनाव आयोग ने अपने साथ-साथ, चुनाव मात्र की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है। जाहिर है कि वह यह इसलिए कर रहा है, क्योंकि उसे कार्यपालिका के शीर्ष पर बैठी मोदी-शाह जोड़ी को खुश करना है, जिसने कानून बदलकर उनकी नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है और ऐसा, वे कानूनी जवाबदारी की परवाह न करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि उसी कानून के जरिए उन्हें चुनाव आयोग में पद पर रहते हुए किए गए कामों के लिए, जीवन भर के कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दे दी गयी है।

यह कुल मिलाकर चुनाव को ही बेमानी बनाकर, जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति में जनतंत्र का ही रास्ता बंद कर दिए जाने की कोशिश है। स्वाभाविक रूप से जनतंत्र की परवाह करने वाली सभी ताकतें, अपनी तमाम भिन्नताओं के बावजूद, जनतंत्र के इस अपहरण के खिलाफ प्रतिरोध के लिए सामने आ रही हैं। इमर्जेंसी का अनुभव गवाह है कि इस देश में जनतंत्र की कद्र करने वाली ताकतों का दायरा बहुत बड़ा है। और यही संघ-भाजपा और उनके मौजूदा निजाम की बौखलाहट का असली कारण है। वे बदनाम करने से लेकर राजकीय-निजी सेनाओं के जरिए दमन तक, अपने सारे हथियार आजमा कर भी इस तूफान को रोक नहीं पाएंगे। यह भी याद रहे कि वे ही हैं, जो हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में, विश्वसनीय चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सत्ता के बल पर जनता की इच्छा को हमेशा के लिए दबा तो नहीं सकते हैं, हां! चुनाव के जरिए उसकी अभिव्यक्त का रास्ता बंद कर के अपने फासीवादी तरीकों से, जनता की इच्छा को अपने प्रकटीकरण के दूसरे रास्तों की ओर जरूर धकेल सकते हैं। चुनावों की विश्वसनीयता और पवित्रता की रक्षा के लिए, आज जो ताकतें लड़ रही हैं, वे ही इसकी इकलौती गारंटी हैं कि भारत में रिजीम चेंज किसी बांग्लादेश या नेपाल की तरह नहीं हो। वर्ना सत्ताधारी संघ-भाजपा तो भारत को बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते पर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके लिए इतिहास का एक ही संदेश है -- सिंहासन खाली करो कि जनता आती है!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ संजय सम्राट की मांग

BS-IV डीजल टैक्सियों और टूरिस्ट बसों पर प्रतिबंध से पर्यटन उद्योग पर संकट: संजय सम्राट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और मुलाकात का समय मांगा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन (रजि.) के अध्यक्ष संजय सम्राट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर BS-IV डीजल टूरिस्ट टैक्सियों और बसों पर प्रस्तावित प्रतिबंध सहित परिवहन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है।

संजय सम्राट ने कहा कि 1 नवंबर 2026 से BS-IV डीजल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध से हजारों ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो सकता है। कोरोना महामारी के दौरान करीब दो वर्ष तक कारोबार प्रभावित रहा। इसके बाद भी पर्यटन व्यवसाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टूरिस्ट वाहन साल में मुश्किल से 5–6 महीने ही काम कर पाते हैं, जबकि बैंक की EMI, टैक्स, बीमा और अन्य खर्च लगातार देने पड़ते हैं।

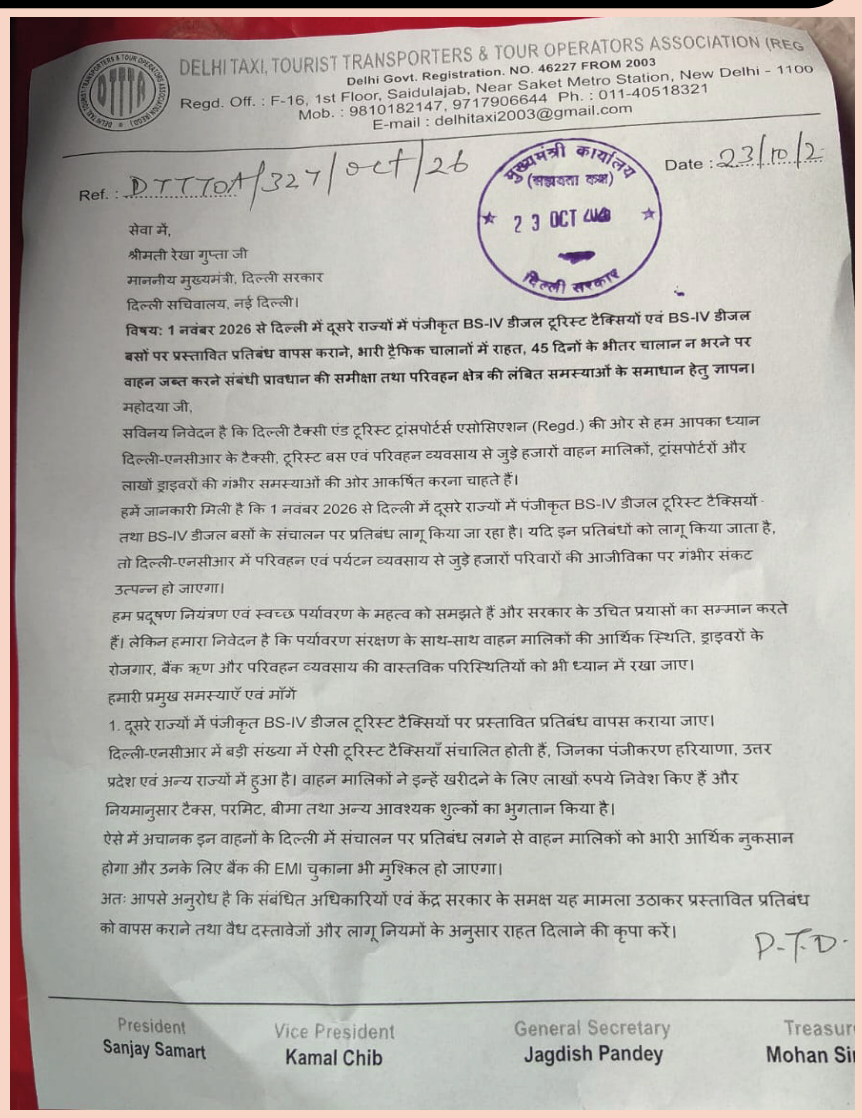
उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों ने लाखों रुपये निवेश करके गाड़ियां खरीदी हैं। ऐसे में अचानक प्रतिबंध लगने से ट्रांसपोर्टरों को भारी आर्थिक नुकसान होगा और हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।

एसोसिएशन ने भारी ट्रैफिक चालानों में राहत, 45 दिनों में चालान का भुगतान न होने पर वाहन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई संबंधी प्रावधानों की समीक्षा, पैनिक बटन/VLTD की लागत तथा अन्य परिवहन समस्याओं के समाधान की भी मांग की है।

संजय सम्राट ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उन्हें जल्द मुलाकात का समय दिया जाए और CAQM के चेयरमैन के साथ एसोसिएशन की बैठक कराई जाए, ताकि परिवहन एवं पर्यटन उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करके व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके।

उन्होंने कहा कि एसोसिएशन प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के साथ ट्रांसपोर्टरों की आर्थिक स्थिति, ड्राइवरों के रोजगार और पर्यटन उद्योग के भविष्य को सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

अध्यक्ष
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन (रजि.



DELHI TAXI, TOURIST TRANSPORTERS & TOUR OPERATORS ASSOCIATION (REG
Delhi Govt. Registration. NO. 46227 FROM 2003
Regd. Off. : F-16, 1st Floor, Saidulajab, Near Saket Metro Station, New Delhi - 1100
Mob. : 9810182147, 9717906644 Ph. : 011-40518321
E-mail : delhitaxi2003@gmail.com

Ref. : DTTOA/327/oct/26 Date : 23/10/2

मुख्यमंत्री कार्यालय (सचिवालय रेखा) 23 OCT दिल्ली सरकार

सेवा में,
श्रीमती रेखा गुप्ता जी
माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

विषय: 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-IV डीजल टूरिस्ट टैक्सियों एवं BS-IV डीजल बसों पर प्रस्तावित प्रतिबंध वापस कराने, भारी ट्रैफिक चालानों में राहत, 45 दिनों के भीतर चालान न भरने पर वाहन जब्त करने संबंधी प्रावधान की समीक्षा तथा परिवहन क्षेत्र की लंबित समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन।

महोदया जी,

सविनय निवेदन है कि दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन (Regd.) की ओर से हम आपका ध्यान दिल्ली-एनसीआर के टैक्सी, टूरिस्ट बस एवं परिवहन व्यवसाय से जुड़े हजारों वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और लाखों ड्राइवरों की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

हमें जानकारी मिली है कि 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-IV डीजल टूरिस्ट टैक्सियों तथा BS-IV डीजल बसों के संचालन पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। यदि इन प्रतिबंधों को लागू किया जाता है, तो दिल्ली-एनसीआर में परिवहन एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा।

हम प्रदूषण नियंत्रण एवं स्वच्छ पर्यावरण के महत्व को समझते हैं और सरकार के उचित प्रयासों का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा निवेदन है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वाहन मालिकों की आर्थिक स्थिति, ड्राइवरों के रोजगार, बैंक ऋण और परिवहन व्यवसाय की वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए।

हमारी प्रमुख समस्याएँ एवं माँगें

1. दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-IV डीजल टूरिस्ट टैक्सियों पर प्रस्तावित प्रतिबंध वापस कराया जाए।

दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में ऐसी टूरिस्ट टैक्सियाँ संचालित होती हैं, जिनका पंजीकरण हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में हुआ है। वाहन मालिकों ने इन्हें खरीदने के लिए लाखों रुपये निवेश किए हैं और नियमानुसार टैक्स, परमिट, बीमा तथा अन्य आवश्यक शुल्कों का भुगतान किया है।

ऐसे में अचानक इन वाहनों के दिल्ली में संचालन पर प्रतिबंध लगने से वाहन मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान होगा और उनके लिए बैंक की EMI चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों एवं केंद्र सरकार के समक्ष यह मामला उठाकर प्रस्तावित प्रतिबंध को वापस कराने तथा वैध दस्तावेजों और लागू नियमों के अनुसार राहत दिलाने की कृपा करें।

P-T-O

President Sanjay Samart | Vice President Kamal Chib | General Secretary Jagdish Pandey | Treasur Mohan Si

शक्तिशाली हो रहा है चक्रवात! ओडिशा पर पड़ सकता है ज्यादा असर



मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संभावित चक्रवात को लेकर जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, 26 अक्टूबर तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में यह एक चक्रवात का रूप ले सकता है। वर्तमान में पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। 24 अक्टूबर तक इसके डिप्रेशन (अवदाब) में बदलने की संभावना है। वहीं, 25 अक्टूबर तक इसके गहरे अवदाब में तब्दील होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, अवदाब में बदलने के बाद ही संभावित चक्रवात की दिशा को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से ओडिशा में 26 अक्टूबर से बारिश शुरू होने की संभावना है। तटीय ओडिशा में बारिश का प्रभाव अधिक रहने का अनुमान है। 27 अक्टूबर तक तेज हवाएं चल सकती हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मौसम विभाग के शुरुआती आकलन के अनुसार, इस संभावित चक्रवात के और अधिक शक्तिशाली होने की आशंका भी जताई जा रही है। संभावित चक्रवात को देखते हुए ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त (SRC) ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।



जीडिमेटला स्थित श्री आईमाताजी बडेर मे स्व . नेमारामजी पंवार की श्रद्धांजलि सभा मे श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए जोगाराम, नवलाराम, वक्ताराम, ताराराम, वीरम धेवर ललित यशवंत, रुघाराम गेहलोत, मांगीलाल सोलंकी सर्व समाज गणमान्य पदाधिकारीयों पारसनाथ चौहान, नेमिचन्द्र गोयल, सोहनलाल हाम्बड़, मांगीलाल काग, प्रेम पंवार, मोहनलाल हाम्बड़, रमेश पंवार ,पुनाराम हाम्बड़, बाबूलाल भायल, धेवरचन्द चोयल ,हीरालाल चोयल जयराम पंवार, नारायणलाल बर्फा, नरेश कुमार सोलंकी, अर्जुनलाल बर्फा, पुनाराम बर्फा ,राजुराम बर्फा, भगवानराम, मोहन हाम्बड़, रुघाराम चोयल , सेसाराम पंवार, चुतराराम सानपुरा, मांगीलाल पंवार , दुर्गाराम सोलंकी , डुगाराम सोलंकी,प्रकाश सोलंकी, केनाराम मुलेवा, उदाराम काग, मोहनलाल काग, देवाराम बर्फा,जयराम परिहार,व अन्य

नाबालिग वाहन चालकों पर STA की नजर, पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना; 25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा लाइसेंस

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों के कारण बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नाबालिग विद्यार्थियों को वाहन चलाकर कोचिंग सेंटर और शिक्षण संस्थानों तक आने से रोकने के लिए STA ने विभिन्न शहरों के कोचिंग सेंटरों को स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के माध्यम से पत्र जारी किए हैं।

इसके अलावा, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और प्रमुख कॉलेजों के अधिकारियों को भी पत्र लिखकर लापरवाही से वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की सलाह दी गई है।

STA के सूत्रों के अनुसार, राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में लगभग 45 प्रतिशत लोग 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं। वहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जुड़ी दुर्घटनाएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सामान्य मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसके बावजूद कई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए दे देते हैं। इससे बच्चे दुर्घटनाओं



का शिकार हो रहे हैं। कम उम्र में ही कई बच्चों की जान चली जाती है, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल होकर दिव्यांग हो जाते हैं। नाबालिग विद्यार्थियों को वाहन चलाने से रोकने के लिए STA ने कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, संबलपुर और राउरकेला जैसे प्रमुख शहरों में संचालित कोचिंग सेंटरों को स्थानीय RTO के माध्यम से पत्र भेजकर अंडरटेकिंग यानी लिखित आश्वासन देने का निर्देश दिया है। कोचिंग सेंटरों को विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर इस विषय में जागरूक करना होगा। अभिभावकों को अपने बच्चों को स्वयं वाहन से कोचिंग सेंटर छोड़ने या उन्हें सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से भेजने की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

STA ने चेतावनी दी है कि अंडरटेकिंग देने के बावजूद यदि विद्यार्थी स्वयं वाहन चलाकर कोचिंग सेंटर आते पाए जाते हैं, तो संबंधित कोचिंग सेंटर के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी निर्देश,

STA ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अधिकारियों को भी पत्र लिखकर विद्यार्थियों को मोटर वाहन कानून और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया है।

हालांकि इन संस्थानों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी बालिग हैं, लेकिन उनमें भी मोटर वाहन कानून के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है। कई विद्यार्थी हेलमेट नहीं पहनते और लापरवाही से वाहन चलाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। STA के अतिरिक्त आयुक्त दीप्तिरंजन पात्र ने बताया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो संबंधित वाहन का पंजीकरण एक वर्ष के लिए रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। दीप्तिरंजन पात्र ने अभिभावकों से अपील की है कि वे इस कानूनी प्रावधान को गंभीरता से लें और अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों तथा कोचिंग सेंटरों को सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है।

भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर अवकाश की मांग तेज, अनुयायियों में निराशा

स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजजी से की 26 अक्टूबर को राजपत्रित अवकाश घोषित करने की मांग

आगरा। रामायण के महान रचयिता, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर अवकाश घोषित न होने से उनके अनुयायियों में निराशा है। भगवान प्रभू श्रीराम के आदर्शों को युगों-युगों तक जनमानस में जीवंत रखने वाले तथा माता सीता और लव-कुश के जीवन से जुड़ी गौरवशाली परंपरा के संवाहक महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रकटोत्सव दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग उठी है।

इसी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ की बैठक आगरा के आईडीएच, राजनगर में हुई। वक्ताओं ने कहा कि भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्रकटोत्सव



केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों से जुड़ा गौरवशाली अवसर है। ऐसे महान महापुरुष के प्रकटोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से उनके योगदान और आदर्शों को व्यापक सम्मान मिलेगा।

बैठक में उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 671/तीन-2025-39(2)/2016, दिनांक 17 नवंबर 2025 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाशों की सूची में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव का अवकाश शामिल नहीं है।

मुख्यमंत्री से तत्काल निर्णय लेने की अपील

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मांग की गई कि 26 अक्टूबर 2026, सोमवार को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव दिवस पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत अवकाश घोषित किया जाए। वक्ताओं का कहना था कि महर्षि वाल्मीकि के ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के अनुरूप उनके प्रकटोत्सव को सरकारी स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए।

बैठक में विनोद इलाहाबादी, सुंदर बाबू चंचल, भुल्ले नरवार, रोहित लवानिया, जयकिशन कछवाह, राजू डागौर, सम्राट चौधरी, अनिल राजौरिया, बसंत लाल पाथरे, रेशम सिंह चाहर, राजेश चौहान, शरद थनवार, सोनू चौहान, अनिल रामपुरिया, सनी चौहान, देवेंद्र देवू, अभिषेक चौहान और कान्हा ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत केरलम के दल का बीएचयू के मालवीय भवन में भव्य स्वागत,विद्यार्थियों ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

(संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी:- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत आयोजित 'युवा संगम' सातवे चरण के तहत केरलम (आईआईटी पलक्कड़) से आए 55 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में भव्य स्वागत किया गया | इस दल में 50 छात्र और 5 शिक्षक शामिल है जिनका नेतृत्व सेलेस्टेट आर और गोपी श्रीकांत रेड्डी कर रहे है | मालवीय भवन में आयोजित समारोह में बीएचयू के नोडल अधिकारी डॉ.बाला लखेंद्र ने अपने स्वागत उद्बोधन के माध्यम से सभी आगंतुक अतिथियों, शिक्षकों एवं केरलम के युवा दल का औपचारिक अभिनंदन किया | उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एकता,भाईचारा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के उद्देश्य से यह दल १8 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर रहेगा | इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित परिसर की भावना को बढ़ावा देते हुए सभी विद्यार्थियों ने मिलकर पौधारोपण भी किया |

कार्यक्रम में छात्र अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टूडेंट्स) प्रो.रंजन कुमार सिंह ने छात्रों का काशी एवं बीएचयू परिसर में स्वागत किया | उन्होंने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास,समृद्ध शैक्षणिक परंपराओं और विशाल परिसर की जानकारी देते हुए छात्रों को बीएचयू भ्रमण के लिए प्रेरित किया | मालवीय भवन के निदेशक डॉ.पतंजलि मिश्र ने आदर्श छात्र जीवन पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ब्रह्मचर्य और नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष जोर दिया | समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों ने केरलम के छात्रों का अभिनंदन करते हुए उन्हें बनारस की प्राचीन सभ्यता,संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से रुबरु कराया | दल के सदस्यों ने काशी की समृद्ध विरासत का अनुभव करने के लिए अस्सी घाट का भी भ्रमण किया | इस अवसर पर मुख्य रूप से बीएचयू के कुलसचिव डॉ.राजेंद्र श्रीवास्तव,उप मुख्य आरक्षाधिकारी प्रो.फतेह बहादुर, समन्वयक डॉ.अशोक कुमार शर्मा सहित सौम्या मुखर्जी,सनिल और श्रीकांत रेड्डी उपस्थित रहे | १4 अक्टूबर को प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गए आदर्श गाँव जयापुर का दौरा कर ग्रामीण विकास कार्यों को समझेगा | १5 अक्टूबर को यह दल लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगा जहाँ वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट करेंगे | लखनऊ प्रवास के दौरान यह दल धर्मनगरी अयोध्या का भी भ्रमण करेगा | १8 अक्टूबर तक चलने वाले इस दौरे के माध्यम से केरलम के युवा बनारस, अयोध्या और लखनऊ की समृद्ध संस्कृति, नवाचार और विकास कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होंगे ||

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023